घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 119- शनिवार 28- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

दिल्ली शराब नीति मामले में के. कविता बरी,बोलीं...'सत्यमेव जयते',सच की हुई जीत...

नई दिल्ली,27 फरवरी 2026। तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और पूर्व सांसद के.कविता ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। उन्होंने यह बयान उस समय दिया,जब दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में उन्हें बरी कर दिया। आबकारी नीति से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की पुत्री के रूप में आरोपों का सामना कर रहीं कविता को अदालत से राहत मिलने के बाद उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए 'सत्यमेव जयते' कहा। मीडिया से बातचीत में कविता ने दावा किया कि पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उन्हें फंसाने की साजिश था। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उन्होंने तेलंगाना की जनता से भरोसा जताया था कि सच की जीत होगी और वह बेदाग साबित होंगी। कविता ने कहा, 'मैं लगातार कहती रही हूं कि मैं धुले हुए मोती की तरह बाहर निकलूंगी और आज सच सामने आ गया है। इस मामले के कारण मुझे और मेरे परिवार को कई महीनों तक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। ' उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और अदालत के फैसले से पहले ही उनके खिलाफ गलत धारणाएं बनाई गईं। अदालत का फैसला आने के बाद कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी 'सत्यमेव जयते' लिखकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कठिन समय में साथ देने वाले समर्थकों और शुभचिंतकों का आभार जताते हुए कहा कि अब वह पहले से अधिक ऊर्जा के साथ जनता की सेवा करेंगी।

बांके बिहारी मंदिर में यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोक,रीलबाजों पर बैन मीडिया के लिए नई गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली,27 फरवरी 2026। विश्व प्रसिद्ध वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रशासन ने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। मंदिर प्रशासन ने यह कदम भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा और भ्रामक जानकारी फैलाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। अब मंदिर परिसर में रील बनाने या अनधिकृत वीडियो शूट करने वाले यूट्यूबर्स का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि अधिकृत और पंजीकृत मीडिया कर्मियों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। मंदिर की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) अशोक कुमार और जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने स्पष्ट किया है कि मंदिर परिसर की मर्यादा,सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि कई सोशल मीडिया संचालक गलत या भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स वीडियो बनाने की होड़ में आम श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कई बार रील बनाने के प्रयास में गलियारों और गर्भगृह के पास भीड़ जमा हो जाती है, जिससे भीड़ प्रबंधन प्रभावित होता है। आगामी रंगभरनी एकादशी और होली पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए यह निर्णय जरूरी माना गया है,ताकि किसी भी प्रकार की भगदड़ या अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त और अधिकृत मीडिया संस्थानों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। अधिकृत मीडिया कर्मी मंदिर परिसर में प्रवेश कर कवरेज कर सकते हैं,ताकि जनता तक सही और प्रमाणिक जानकारी पहुंच सके और अफवाहों पर नियंत्रण लगाया जा सके। होली और रंगभरनी एकादशी के मद्देनजर वृंदावन में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर आयुक्त जग प्रवेश ने वृंदावन क्षेत्र का निरीक्षण कर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सीवर व्यवस्था की जांच की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था उच्च स्तर की होनी चाहिए और मार्गों पर कूड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए।

परिवार संग होली मना सकेगा नीतीश कटारा हत्याकांड का दोषी

सुप्रीम कोर्ट ने दी सात दिन की फरलो

नई दिल्ली,27 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी विकास यादव की याचिका मंजूर की। विकास यादव 2002 में व्यवसायी नीतीश कटारा की हत्या के लिए 25 साल की जेल की सजा काट रहा है। उसने जेल से होली पर परिवार के साथ समय बिताने के लिए रिहाई की मांग की थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि विकास यादव ने अब तक 23 साल की सजा पूरी कर ली है। इसलिए उसे सात मार्च तक रिहाई की अनुमति दी गई है। इस दौरान वह अपने परिवार के साथ होली मना सकेगा। बेंच ने कहा, होली के समय परिवार के साथ समय बिताने के लिए फरलो का आवेदन किया गया है। मामले के मापदंडों में प्रवेश किए बिना हम याचिकाकर्ता को सात मार्च तक फरलो (अस्थायी रिहाई) की अनुमति देते हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने विकास यादव की रिहाई के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज किया। बेंच ने कहा, क्या आप उसे फांसी देना चाहते हैं? 23 साल बाद आप अभी भी मामला खड़ा करना चाहते हैं। हमें चीजों को आगे बढ़ने देना चाहिए। जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से कहा कि इस तरह की रिहाई कभी-कभी दोषी के सुधार में मदद कर सकती है।

शराब घोटाले में केजरीवाल-मनीष सिसोदिया बरी

कोर्ट बोला...सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ी,जांच एजेंसी ने 6 घंटे बाद ही हाईकोर्ट में अपील की...

नई दिल्ली,27 फरवरी 2026। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा- दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है,आरोप साबित नहीं होता। सीबीआई ने साजिश गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। सीबीआई ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। जांच एजेंसी ने करीब 6 घंटे बाद दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की है। वहीं,बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा...मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल,मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। वहीं,कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा...हमें एक बार फिर गर्व हो रहा हैं अपने संविधान पर और बी.आर.अंबेडकर पर, जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया। सच की फिर से जीत हुई है।

कोर्ट ने सबूतों को बताया कमजोर

कोर्ट की टिप्पणी से यह स्पष्ट हुआ कि दाखिल की गई चार्जशीट में कई खामियां थीं। अदालत ने कहा कि कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी आधार पर राहत दी गई। हालांकि,जांच एजेंसी का कहना है कि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगी। सीबीआई के वकीलों की ओर से संकेत दिया गया है कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी।

कोर्ट ने झूठ का किला ढहा दिया

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने झूठ का किला ढहा दिया। देशभर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले चार साल से ईडी,सीबीआई और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराबा घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया। सीबीआई,ईडी ने उसमें चार्जशीट दाखिल की। आज कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा भी चलाया जा सके। कोर्ट का कहना है कि इतना गलत, फर्जी केस है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। यह पूरा षड्यंत्र किसने और क्यों रचा? यह पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने रचा, उन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए।

सबूतों के अभाव में बरी हुए केजरीवाल : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी (आआपा) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले के सीबीआई से संबंधित मामले में बरी किए जाने पर कहा कि अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह एक तकनीकी मामला है और इसमें सैकड़ों मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट किए गए। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सबूतों के अभाव में अदालत से बरी हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि सबूतों को नष्ट करने के लिए 173 मोबाइलों को नष्ट किया गया। भाजपा के नेता हर समय सबूतों को नष्ट करने के बात कहते रहे। आआपा नेताओं की सच्चाई दिल्ली की जनता जानती है,इसलिए उन्होंने सजा देकर आआपा को सत्ता से बाहर किया। तिवारी ने कहा कि कानून को सबूत नष्ट करके ज्यादा देर तक भ्रमित नहीं कर सकते हैं। सीबीआई उच्च अदालत जा रही है और दिल्ली को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों को सजा जरूर मिलेगी।

मोदी-शाह ने षड़यंत्र रचा,अदालत के फैसले के बाद दिल से बड़ा बोझ उतरा : केजरीवाल

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ साजिश रची। वे आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए तो खत्म करने जुट गए। दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा... आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया है। आपने इतने केस बनाए। आपने हमारे पीछे ईडी,सीबीआई,पुलिस छोड़ी। एक समय आम आदमी पार्टी के टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। पूर्व सीएम ने कहा...अब तो केवल कत्ल कराकर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं। बिना कत्ल कराए ये लोग केजरीवाल को संभाल नहीं सकते हैं। मोदी और शाह के षड़यंत्र का खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे हैं।

आप पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई...

केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी और शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में फिर से चुनाव कराने की चुनौती भी दी। केजरीवाल ने दावा किया कि यदि भाजपा को दस से अधिक सीटें मिलीं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल जाने से फर्क पड़ता है और यह उनके परिवार को प्रभावित करता है। केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर दिल्ली की हालत खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने झूठ का किला ढहा दिया है। कोर्ट के करीब 600 पेज के आदेश में मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं मिले।

फाइटर हेलिकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली मुर्मू पहली राष्ट्रपति

कॉकपिट से देश को मैसेज-वीर सैनिकों को गर्व के साथ धन्यवाद- जय हिंद,जय भारत

जैसलमेर,27 फरवरी 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। वे हेलिकॉप्टर प्रचंड में बतौर को-पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ने उड़ान के दौरान हेलिकॉप्टर के कॉकपिट से सैल्यूट किया। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी थीं। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह करीब 9:15 बजे जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पहुंची थीं। सेना के अधिकारियों ने उन्हें हेलिकॉप्टर के बारे में ब्रीफिंग दी। इसके बाद राष्ट्रपति हेलिकॉप्टर के कॉकपिट में बैठीं। फिर सुबह करीब 10.15 बजे ग्रुप कैप्टन एन.एस. बहुआ के साथ हेलिकॉप्टर में उड़ान भरी। हेलिकॉप्टर में 25 मिनट उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा लिया। जैसलमेर के सोनार दुर्ग के ऊपर 'प्रचंड' हेलिकॉप्टर में उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति ने रेडियो के माध्यम से देश के नाम संदेश दिया।

तीन साल पहले रक्षा मंत्री ने भरी थी उड़ान

तीन साल पहले नवरात्रि पर अष्टमी के दिन हेलिकॉप्टर प्रचंड एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसमें उड़ान भरी थी। उन्होंने कहा था...'प्रचंड को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्रि से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती है। यह भारत का विजय रथ है। एलसीएच सारी चुनौतियों पर खरा उतरा है। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। इसके नाम के साथ भले ही लाइट जुड़ा हो,लेकिन इसका काम भारी है। '

राष्ट्रपति को गिफ्ट की उनकी तस्वीर

एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने राष्ट्रपति को मोमेंटो भेंट किया और 'प्रचंड' हेलिकॉप्टर के साथ ली गई उनकी पहली तस्वीर भी उन्हें गिफ्ट दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति ने पायलट और अन्य वायुसेना अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाई। जैसलमेर के सोनार दुर्ग के ऊपर 'प्रचंड' हेलिकॉप्टर में उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेडियो के माध्यम से देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा...मैं आज प्रचंड हेलिकॉप्टर में उड़ान भर रही हूं। प्रचंड हेलिकॉप्टर आत्मनिर्भरता का प्रबल प्रतीक है। मैं इस समय जैसलमेर के प्रसिद्ध किले के ऊपर से उड़ान भर रही हूं। मैं देश के वीर सैनिकों को गर्व के साथ धन्यवाद देती हूं। मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

राष्ट्रीय बजट अल्पकालिक व्यापार दस्तावेज नहीं,नीतिगत रोडमैप : पीएम मोदी

नई दिल्ली,27 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बजट का आकलन उसके प्रत्यक्ष लाभ या प्रभाव से नहीं बल्कि इसमें निहित नीतिगत प्रयासों से होना चाहिए। असल में राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापार दस्तावेज़ नहीं होता है। यह एक नीतिगत रोडमैप होता है। ऐसे में बजट की प्रभावशीलता का आंकलन ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वीडियो कांफ्रेंसिंग से बजट बाद वेबिनार-'विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी,सुधार और फाइनेंस' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट को ढांचागत सुविधाओं के विस्तार,धन प्रवाह, जीवन जीने में आसानी,पारदर्शिता के साथ शासन और लोगों के लिए नए-नए अवसर बनाने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश रिफोर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमें नीतिगत मंशा और उससे हासिल उपलब्धि पर भी फोकस करना है। उन्होंने कहा कि हमें एआई,ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग कर पारदर्शिता,गति और जवाबदेही बढ़ानी ही होगी और साथ ही शिकायत निवारण प्रणालियों से प्रभाव की निरंतर निगरानी भी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को सरकार के ढांचागत सुविधाओं में निवेश का लभा उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में ढांचागत सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट 2 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश निजी क्षेत्र के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि उद्योग और वित्तीय संस्थान भी नई ऊर्जा के साथ आगे आएं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि परियोजनाओं की मंजूरी और मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है।

उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

प्रयागराज,27 फरवरी 2006। उच्च न्यायालय ने पॉस्को एक्ट में दर्ज एफआईआर मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फिलहाल राहत मिल गई है। शुक्रवार को न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद अपना आदेश रिजर्व कर लिया है,लेकिन आदेश आने तक उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। दरअसल, पॉस्को एक्ट में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और उच्च न्यायालय ने अविमुक्तेश्वरानंद की अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए आदेश को सुरक्षित कर लिया है। गौरतलब है कि आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के आदेश के अनुपालन मेंअविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बीते रविवार झूंसी थाने में पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। झूंसी पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में पूछताछ कर चुकी है।

कोलकाता सहित बंगाल के कई जिलों में भूकंप, 5.4 तीव्रता

कोलकाता,27 फरवरी 2026। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित कई जिलों में शुक्रवार दोपहर करीब 1.30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के ढाका स्थित अगरगांव में था।

रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। पश्चिम बंगाल से अगरगांव की दूरी लगभग 26 किलोमीटर बताई जा रही है। झटके इतने तेज थे कि कोलकाता में बहुमंजिला इमारतें कुछ सेकेंड तक हिलती रहीं। अचानक कंपन महसूस होते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव-2026 देश के लिए बनेगा आदर्श उदाहरण : ज्ञानेश कुमार

नई दिल्ली,27 फरवरी 2026। तमिलनाडु में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव-2026 को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राज्य में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव पूरे देश के लिए एक आदर्श उदाहरण साबित होगा। दो दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। दिल्ली लौटने से पूर्व उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए चुनाव प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष,पारदर्शी एवं कानून के दायरे में संपन्न कराए जाएंगे। मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे तथा संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा और उनके सुरक्षित रख-रखाव के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि मतदान कर्मियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि वे बिना किसी दबाव या भय के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। मतदान की प्रगति से संबंधित जानकारी प्रत्येक दो घंटे में ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया की सतत निगरानी की जाएगी तथा आवश्यक होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

इंसेफ्लाइटिस पर निर्णायक विजय

ये सब सहकारी संघवाद का सफल उदाहरण बने,जिसने दशकों की उपेक्षा से शिकार हो रहे हजारों जीवन बचाए। उत्तर प्रदेश का यह लक्षित हस्तक्षेप राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का उत्प्रेरक बना और उसे हेल्थकेयर एवं मेडटेक का उभरता हुआ केंद्र बना दिया...

एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सफलता हाल के समय की सबसे उल्लेखनीय जनस्वास्थ्य उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कठोर क्रियान्वयन क्षमता ने राज्य को 2017 में 5,400 से अधिक मामलों और 650 से अधिक मौतों से 2024 में मामलों में तीव्र गिरावट और शून्य मृत्यु तक पहुंचा दिया। यह एक ऐसी सफलता है जो कभी भारत के सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांकों से जकड़े राज्य के खाते में गई है।

चार दशकों तक इंसेफ्लाइटिस ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रखा था। गोरखपुर इसका केंद्र रहा,जबकि कुशीनगर,महाराजगंज,देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती जैसे जिले इसकी चपेट में रहे। यह बीमारी बच्चों और युवाओं को अचानक तेज बुखार और मानसिक भ्रम के साथ जकड़ लेती थी,जो अक्सर मौत का कारण बन जाती थी। जो बच जाते, वे जीवनभर न्यूरोलाजिकल और शारीरिक अक्षमता से पीड़ित रहते। वर्ष 2017 तक इस बीमारी ने लगभग 50 हजार जानें ले लीं,जिनमें अधिकांश बच्चे थे। यह आंकड़ा न केवल चिकित्सा विफलता,बल्कि दशकों की प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का प्रतीक था। दूषित पानी, कुपोषण, गंदगी और अस्वच्छ जीवन स्थितियों ने संक्रमण को बढ़ावा दिया, ऊपर से पूरी तरह से जर्जर स्वास्थ्य ढांचे ने हालात को काफी गंभीर बना दिया था। राज्य में तब बच्चों के लिए आईसीयू का अभाव, कमजोर लैब सुविधाएं, अपर्याप्त एंबुलेंस सेवाएं आम बात थीं। यही कारण था कि 2017 तक 28 जिले लगातार संक्रमित रहे और इंसेफ्लाइटिस राज्य की विफलता का प्रतीक बन गया। इसी पृष्ठभूमि में 2017 के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णायक कार्रवाई का वादा किया।

वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन प्राथमिकता बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इसे मिशन मोड पर लिया गया। चुनौती केवल बीमारी से लड़ने की नहीं थी,बल्कि भरोसेमंद स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने की भी थी। इसके बाद जो हुआ वह किसी बिखरे हुए हस्तक्षेप या संकट-प्रतिक्रिया तंत्र तक सीमित नहीं था,बल्कि केंद्र की सतत निगरानी, संसाधन आवंटन, विभागीय समन्वय और रणनीतिक नेतृत्व पर आधारित एक व्यापक और व्यवस्थित सुधार कार्यक्रम था। सात विभागों को जोड़कर समग्र योजना बनी। वर्ष 2019 में गोरखपुर में एम्स की स्थापना,आइसीएमआर की भूमिका मजबूत हुई। सक्रिय सर्वेक्षण से इंसेफ्लाइटिस के कारणों और जोखिमों की पहचान हुई,लैब अपग्रेड हुए,डायग्नोस्टिक किट विकसित हुईं। बीआरडी मेडिकल कालेज,गोरखपुर को उन्नत किया गया,प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बने,एंबुलेंस सेवाएं शुरू हुईं।

रमन की विरासत और नारी नेतृत्वः विकसित भारत का वैज्ञानिक युग

योगेश कुमार गोयल
नजफ्फगढ़,नई दिल्ली

सपनों को हकीकत में बदलने की कुंजी है विज्ञान

मानव जीवन को विज्ञान ने आज बेहद आसान और सुविधाजनक बना दिया है। युवाओं की विज्ञान के प्रति आज के समय में कितनी रूचि है,इसी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। युवाओं के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के दिलोदिमाग में विज्ञान के प्रति अधिकाधिक रूचि जागृत करने के लिए ही प्रतिवर्ष 28 फरवरी को 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' मनाया जाता है। दरअसल इस दिवस के जरिये बच्चों को विज्ञान को बतौर कैरियर चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि देश की आने वाली पीढ़ी विज्ञान के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सके और देश प्रगति के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए वर्ष 1986 में भारत सरकार को कहा गया था और सरकार द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद से 28 फरवरी 1987 से प्रतिवर्ष इसी दिन भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक महान कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता रहा है। यह दिवस भारत के महान् वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री सर सी.वी.रमन की खोज'रमन प्रभाव' को सदैव याद रखने और विश्व पटल पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले इस वैज्ञानिक को सम्मान देने के लिए उनकी स्मृति में मनाया जाता है। दरअसल सर सी वी रमन भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में पहले ऐसे भारतीय थे,जिन्होंने भारत में ऐसे आविष्कार पर शोध किया था।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में 1907 से 1933 तक सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन ने कार्य किया था। उस दौरान उन्होंने भौतिकी के कई बिन्दुओं पर शोध किया था, जिसमें से'रमन प्रभाव'(प्रकाश के फैलने पर प्रभाव,जब विभिन्न वस्तुओं के द्वारा उसे गुजारा जाता है) उनकी महान सफलता और खोज बनी,जो न केवल विज्ञान जगत में लोकप्रिय हुआ बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी इस खोज को सराहा। सर सी.वी.रमन की यह खोज 28 फरवरी 1928 को दुनिया के सामने आई थी,जिसके बाद पूरी दुनिया में उनकी इस खोज ने तहलका मचा दिया था। उनके इसी बड़े आविष्कार के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला 'नोबेल पुरस्कार'दिया गया था। वे एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे,जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव हासिल हुआ था।'रमन प्रभाव'

खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार के अलावा भी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात् भारत लौटने पर उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे न जाने कितने ही रमन सुविधाओं और अवसरों के अभाव में यूं ही अपनी प्रतिभा गंवा देते हैं,जिससे केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नुकसान है, जिसे हमें रोकना होगा।'' वर्ष 2013 से अमेरिकन केमिकल सोसायटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक केमिकल लैंडमार्क के रूप में 'रमन प्रभाव' को नामित किया गया।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष एक निर्धारित थीम के तहत मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय है 'विज्ञान में महिलाएंः विकसित भारत को उत्प्रेरित करना'। 2023 से 2025 तक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्रमशः 'वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान','विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक' और 'विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना' थीम के साथ मनाया गया था। वर्ष 2022 की थीम थी 'सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण' और वर्ष 2021 की थीम थी 'एसटीआई का भविष्य : शिक्षा कौशल और कार्य का प्रभाव'। एसटीआई का अर्थ है साइंस, टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यह विषय शिक्षा कौशल और कार्य पर विज्ञान, प्रोद्यौगिकी और नवाचार (एसटीआई) के भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की वर्ष 1999 से लेकर अब तक की थीम पर नजर डालें तो वर्ष 1999 का विषय था 'हमारी बदलती धरती'। वर्ष 2000 का विषय था 'मूल विज्ञान में रूचि उत्पन्न करना,2001 का 'विज्ञान शिक्षा के लिए सूचना तकनीक', 2002 का 'पश्चिम से धन', 2003 का 'जीवन की रूपरेखा : 50 साल का डीएनए और 25 वर्ष का आईवीएफ', 2004 का 'समुदाय में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना', 2005 का 'भौतिकी को मानना', 2006 का 'हमारे भविष्य के लिए प्रकृति की परवरिश करें',2007 का 'प्रति द्रव्य पर ज्यादा फसल',2008 का'पृथ्वी ग्रह को समझना',2009 का 'विज्ञान की सीमा को बढ़ाना',2010 का 'दीर्घकालिक विकास के लिए लैंगिक समानता, विज्ञान और तकनीक, 2011 का 'दैनिक जीवन में रसायन', 2012 का 'स्वच्छ ऊर्जा विकल्प और परमाणु सुरक्षा',2013 का 'अनुवांशिक संशोधित फसल और खाद्य सुरक्षा', 2014 का 'वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करना',2015 का 'राष्ट्र निर्माण के लिए विज्ञान', 2016 का 'देश के विकास के लिए वैज्ञानिक मुद्दों पर सार्वजनिक प्रशंसा बढ़ाने के लक्ष्य', 2017 का'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकलांग व्यक्तियों के लिए', 2018 का 'एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' तथा वर्ष 2019 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय 'लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग' था। देश में अन्य क्षेत्रों के अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं के योगदान के मद्देनजर उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम रखी गई 'विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं' (वूमेन इन साइंस)।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों को हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों की महत्ता से परिचित कराना होता है,इसके अलावा वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों को अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित करना भी इसका अहम उद्देश्य है। विज्ञान के विकास के लिए नई तकनीकों को लागू कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने जैसे उद्देश्य राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के आयोजन में निहित हैं। विज्ञान के जरिये ही वैज्ञानिकों ने नई-नई तरह की तकनीकों का आविष्कार किया है और वैज्ञानिकों ने इन खोजों के जरिये मानव जीवन को बहुत बेहतर बना दिया है। इसी विज्ञान के जरिये हम रोबोट, कम्प्यूटर इत्यादि बनाने में सफलता प्राप्त करने के अलावा अंतरिक्ष तक में पहुंच गए हैं और असंभव दिखने वाले कार्यों को भी विज्ञान की मदद से ही संभव बनाते रहे हैं। विज्ञान की मदद से ही बनाई गई प्रतिदिन बहुत सारी तकनीकों और वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में करते भी हैं। ऐसे में हम सभी के लिए हमारे जीवन में विज्ञान के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। हमारा समाज 21वीं सदी में जिस प्रकार अंधविश्वासों के साये में जीता है, ऐसे में विज्ञान की महत्ता समझते हुए समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हुए इन अंधविश्वासों के निर्मूलन की जिम्मेदार हम सबकी है।

जीवन में वैज्ञानिक विवेक एवं दृष्टिकोण आवश्यक

प्रमोद दीक्षित मलय
बांदा,उत्तरप्रदेश

विज्ञान मानव को जीवन जीने की एक दृष्टि देता है। चिंतन की आधारभूमि भेंट कर चलने को उजास भरा पथ प्रदान करता है। वास्तव में विज्ञान जीवन से जडता,अविद्या,अंधविश्वास,अतार्किता एवं संशय से मुक्ति का नाम है। विज्ञान व्यक्ति को तर्कशील एवं प्रयोगधर्मी बनाकर सवाल खड़े करने की सामर्थ्य पैदा करता है। विज्ञान मानवीय मेधा का उच्चतम आदर्श है। वसुधा के सौंदर्य को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए प्राणिमात्र के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपभोग का मार्गदर्शन ही विज्ञान है। विज्ञान में समस्या है तो समाधान भी, कल्पना है तो प्रयोग भी। सवाल हैं तो उत्तरों की तह तक पहुंच सत्य का साक्षात्कार करने का सत्संकल्प भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के माध्यम से हम इस भाव एवं चेतना को सिंचित कर समृद्ध करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा युवाओं एवं बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विज्ञान अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से 1986 से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी,1928 को ही सी.वी. रमन ने लोक सम्मुख अपनी विश्व प्रसिद्ध खोज'रमन प्रभाव' की घोषणा की थी।'रमन प्रभाव' के लिए ही 1930 में सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सी.वी. रमन एशिया के पहले भौतिक शास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अमेरिकन केमिकल सोसायटी ने 1998 में 'रमन प्रभाव' को अन्तरराष्ट्रीय विज्ञान के इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वास्तव में 'रमन प्रभाव' के स्मरण के साथ ही मानव जीवन के सम्यक विकास के लिए वैज्ञानिक विवेक, चिंतन एवं दृष्टिकोण अपनाने का दिन है,जिसकी हमें जरूरत है।

चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवम्बर,1888 को तमिलनाडु में कावेरी के तट पर स्थित तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपकी माता पार्वती अम्मा कुशल गृहिणी एवं पिता चन्द्रशेखर भौतिकशास्त्र एवं गणित के प्राध्यापक थे। घर पर एक समृद्ध लघु पुस्तकालय था तो तार वाद्ययंत्रों का संचय भी। संगीत में रुचि के चलते वीणा वादन पिता जी की नित्य साधना थी। वीणा के तारों के कम्पन से निकली मधुर ध्वनि बालक रमन को अपनी ओर खींचती। वह सोचते कि इन

तारों को छेड़ने से एक विशेष लय, प्रवाह, आरोह-अवरोह में मनमोहक ध्वनि कैसे उत्पन्न हो सकती है। यही जिज्ञासा बाद में उनके ध्वनि सम्बंधी शोधों का आधार भी बनी। चार वर्ष की उम्र में ही पिता का तबादला विशाखापट्टनम हो जाने से रमन की प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं शुरू हुई। यहां घर के सामने लहराता सागर का नीला जल रमन का ध्यान आकर्षित करता। बालमन सोचता कि घर और सागर के जल में यह अन्तर कैसे। मकान की खिड़की से वह सागर की लहरों को अठखेलियां करते देखते रहते मानो जल के नीलेपन के रहस्य का कोई तोड़ खोज रहे हों। रमन ने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1903 में बी.ए. में प्रवेश लिया और विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आकर गौरव अर्जित किया। 1907 में एम.ए. गणित प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण किया। परास्नातक करते समय ही 1906 में 'प्रकाश विवर्तन' विषय पर शोध पत्र लिखा जो लंदन से प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध पत्रिका 'फिलसोफिकल मैग जीन' में छपा। 1907 में ही आपने असिस्टेंट एकाउंटेंट जनरल के रूप में कलकत्ता में कार्यभार ग्रहण किया। पर रमन का मन तो विज्ञान की दुनिया में ही रमा था। फलतः एक दिन कार्यालय से घर आते समय वर्ष 1876 में स्थापित 'इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस' की प्रयोग शाला में सुबह-शाम चार-चार घंटे 'ध्वनि में कम्पन एवं कार्य' के क्षेत्र में प्रयोग करने लगे। वह स्कूली बच्चों को प्रयोगशाला लाकर विज्ञान के विभिन्न प्रयोग करके दिखाते ताकि बच्चे विज्ञान की दुनिया को करीब से देख-परख सकें।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी के कहने पर 1917 में आपने नौकरी से त्यागपत्र देकर भौतिकी का प्राध्यापक बनना स्वीकार कर लिया। 1921 में ब्रिटेन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु ऑक्सफोर्ड जाना हुआ। लौटते समय भूमध्य सागर के जल का नीलापन देखकर आप आश्चर्यचकित रह गए। विचार किया कि समुद्र के जल में नीलापन किस कारण से है। उपकरण लेकर आप जहाज के डेक पर आ गये और घंटों सिन्धु जल का अवलोकन-निरीक्षण और प्रयोग करते रहे। इस दौरान पूर्व में विज्ञान वेत्ताओं द्वारा खोजे गये सिद्धांत और निष्कर्ष आंखों के सामने घूमते रहे कि जल का नीलापन समुद्र के अन्दर से प्रकट हो रहा है। पर आप उनसे सहमत नहीं हो पा रहे थे। तब रमन ने इस रहस्य की खोज करने का संकल्प लिया और भारत आकर आपने प्रयोगशाला में 1921 से 1927 तक शोध किया जिसकी परिणति 'रमन प्रभाव' के रूप में हुई। 'रमन प्रभाव' प्रकाश का विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर उसमें होने वाले भिन्न-भिन्न प्रकीर्णन के कारणों का अध्ययन है। सात साल की साधना का फल 'रमन प्रभाव' पर आधारित शोध पत्र 'नेचर' पत्रिका में सर्वप्रथम छपा था। 1924 में आपको रॉयल सोसायटी ऑफ लंदन का फैलो बनाया गया। 1927 में जर्मनी ने जर्मन भाषा में भौतिकशास्त्र का बीस खंडों का एक विश्वकोश प्रकाशित किया। इसमें वाद्य यंत्रों से सम्बंधित आठवें खंड का लेखन रमन द्वारा किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इस विश्वकोश को तैयार करने वाले आप एकमात्र गैर जर्मन व्यक्ति थे। उनके 2000 शोध पत्र विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए। 1948 में आपने सेवानिवृत्ति के बाद बेंगलुरु में 'रमन शोध संस्थान' की स्थापना की।

भारत सरकार ने 1954 में महान कर्मयोगी विज्ञानी रमन के योगदान और वैज्ञानिक उपलब्धियों का वंदन करते हुए 'भारत रत्न' पुरस्कार प्रदान किया। रूस ने 1957 में 'लेनिन शंन्ति पुरस्कार' भेंटकर सम्मानित किया। संचार मंत्रालय ने 20 पैसे का एक टिकट जारी कर आपकी स्मृति को अक्षुण्ण बना दिया। विश्व का यह महान भौतिकविद् 21 नवम्बर, 1970 को अपना लौकिक जीवन पूर्ण कर हमें अकेला छोड़ अंतिम यात्रा पर प्रस्थान कर गया। लेकिन जब तक दुनिया में भौतिकी का अध्ययन होता रहेगा, तब तक 'रमन प्रभाव' अमर रहेगा और चन्द्रशेखर वेंकट रमन भी कोटि उरों में जीवित एवं श्रद्धास्पद बने रहेंगे।।

आम आदमी क्या करें

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर,बिहार

आज मैं बिहार सरकार से एक मांग करती हूं क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर जिले से हूं तो मैं मुजफ्फरपुर की ही समस्या के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। बिहार की राजधानी है पटना लेकिन मुजफ्फरपुर से पटना जंक्शन तक जाने के लिए सुबह में मात्र एक गाड़ी चलती है वो भी नौ बजकर तीस मिनट पर और अक्सर ट्रेन विलंब से ही चलती है तो अब जरा सोचिए जो लोग मुजफ्फरपुर से पटना में नौकरी या पढ़ाई कर रहे है, उनको पटना जाने में कितनी समस्या होती होगी और यह बात हर इंसान जानता है कि एक विद्यार्थी को या फिर पेशेवर लोगों को सुबह नौ बजे तक अपने ऑफिस, स्कूल,महाविद्यालय पहुंचना होता है अगर वो विलंब से पहुंचते हैं तो कुछ के वेतन कट जाते हैं तो कुछ को पनिशमेंट मिलता हैं। तो अब आप सब बताइए कि सुबह के नौ बजकर तीस मिनट वाली पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से कभी कोई विद्यार्थी या नौकरी करने वाले सदस्य जाएगे। मेरा उत्तर है नहीं क्योंकि जब तक ये ट्रेन पटना पहुँचाएगी तब तक लंच ब्रेक हो जाता है। अब सोचिए, अगर मुजफ्फरपुर से पटना जंक्शन के लिए सुबह में कोई ट्रेन होती तो लोग बहुत कम पैसे में पटना पहुंच जाते और समय की भी बर्बादी नहीं होती। जिन्हें प्रत्येक दिन पटना आना-जाना होता है, वो अधिक पैसा खर्च करके पटना आते-जाते हैं खासकर नौकरी या पढ़ाई करने लोग। अब जरा ये भी सोचिए एक आम आदमी जिसकी सीमित वेतन हो,उसे अपना घर चलना होता है,अपना परिवार चलाना होता है,बच्चों की पढ़ाई देखनी होती और अन्य सुविधाएं भी देखनी होती हैं। ऐसे में अगर एक इंसान हर रोज बस का भाड़ा देने लगे तो उसे कितना भाड़ा पड़ जाता है और अगर सुबह में मुजफ्फरपुर से पटना तक के लिए ट्रेन होती तो विद्यार्थी और जो भी पेशेवर लोग हैं वो ट्रेन का पास बनवा लेते और कम पैसे में वो रोज पटना आते -जाते। सोचिए एक आम इंसान के कितने पैसों की बचत हो सकती है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुजफ्फरपुर से कई लोग हाजीपुर तक ट्रेन ले लेते हैं और उसके बाद हाजीपुर से पटना जाने के लिए ऑटो वाले अनजान लोगों से 80,90 कभी-कभी 100 भी मांग लेते हैं और आमतौर पर पिंक बस 37 रूपया लेती है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए नगर बस की भी सुविधा है। लेकिन यह भी तो सोचिए एक महिला जो अपने घर से लड़कर पढ़ाई की, नौकरी की,वो हर रोज पैसा खर्च करके परेशानियां को झेलते हुए पटना जंक्शन पहुंचती हैं, और वहाँ से अपने ऑफिस जाकर काम करती है फिर उतना ही वापस खर्च करके घर वापस होती हैं। अगर वो एक दिन में सिर्फ आने जाने में दो सौ खर्च करेगी, तो महिने का छह हजार खर्च कर देती हैं और पुरुषों का उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। तो बताए क्या करे आम इंसान,नौकरी-पढ़ाई करे या आने- जाने में खर्च होने वाले पैसे को कमाए। जैसे कलकाता में हर छोटे स्टेशन पर जाने के लिए ट्रेन की सुविधा है वैसे ही पटना में होना चाहिए ताकि कोई भी कम पैसे में आ जा सकें और आम इंसान को राहत मिले।

कविता

एहसासों की भाषा

केशी गुप्ता
द्वारका,नई दिल्ली

एहसासों की भाषा अलग है यारों
समझने वाले बहुत कम है यारों
लफ़्ज़ मेल खाएं जो इन से यारों
दिल में उतरते हैं सीधे फिर यारों

मोहब्बत में एहसास जरूरी है यारों
इबादत बिना एहसास नहीं कुछ यारों
धड़कन जोड़ी हुई हर एहसास से यारों
तभी तो जोड़ते हैं दिल दिल से यारों

एहसास जीवन की वो कड़ी है यारों
जीवन को जीवन से जुड़े जो यारों
अपने पराए की दूरी मिटाते जो यारों
एहसास हमें इंसान बनाते हैं यारों

युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन विवाद में...

सुभाष बुड़ावनवाला
रतलाम,मध्यप्रदेश

एआई सम्मेलन में युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन ने केवल एक क्षणिक राजनीतिक विवाद को जन्म नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस की रणनीतिक दिशा और संगठनात्मक परिपक्वता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। किसी वैश्विक महत्व के मंच पर,जहां भारत की तकनीकी और नीतिगत छवि दांव पर हो,इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन विपक्ष की गंभीरता को कमज़ोर करता है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, किंतु उसके स्वरूप और समय की उपयुक्तता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार निराशाजनक परिणामों का सामना करना पड़ा। 2014 में पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई थी, 2019 में यह संख्या 52 तक पहुंची,जबकि 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं। यह सुधार अवश्य है, किंतु पार्टी अब भी स्पष्ट बहुमत से बहुत दूर है। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने संसदीय परंपरा का सम्मान करते हुए राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार किया। यह कदम विपक्षी एकता की भावना को दर्शाता है। हालांकि,व्यवहारिक राज नीति में केवल पद प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता; सहयोगियों को साथ लेकर चलना भी उतना ही आवश्यक है। कांग्रेस पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वह स्वयं को स्वाभाविक

रूप से विपक्ष का केंद्रीय स्तंभ मानती है और अन्य दलों से अनुसरण की अपेक्षा करती है। जबकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अत्यंत बढ़ चुका है। तृणमूल कांग्रेस नेशनल कांग्रेस जैसे दल मूलतः कांग्रेस से अलग होकर ही बने, परंतु आज वे अपने-अपने राज्यों में मजबूत जनाधार रखते हैं।
विपक्षी गठबंधन, जिसे प्रायः 'इंडिया' गठबंधन कहा गया, विविध विचारधाराओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समुच्चय है। ऐसे गठबंधन को टिकाऊ बनाने के लिए विनम्रता, संवाद और सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल या परिवार विशेष के प्रति अनिवार्य निष्ठा की अपेक्षा की जाए, तो स्वाभाविक रूप से असंतोष पनपता है। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व का केंद्रीकरण लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, विशेषकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका को लेकर।

दूसरी ओर, भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का प्रभुत्व लगातार तीसरे कार्यकाल तक बना रहना यह दर्शाता है कि मतदाता स्थिरता और स्पष्ट नेतृत्व को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष यदि केवल व्यक्तिगत आलोचना तक सीमित रह जाता है और वैकल्पिक नीतिगत दृष्टि प्रस्तुत नहीं करता, तो वह जनसमर्थन अर्जित करने में कठिनाई महसूस करेगा।
कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है–एक ओर उसे अपने संगठन को जमीनी स्तर पर पुनर्गठित करना है, दूसरी ओर सहयोगी दलों के साथ समानता और सम्मान के आधार पर संबंध स्थापित करने हैं। यदि पार्टी अपने घटते प्रभाव को स्वीकार कर यथार्थवादी रणनीति अपनाती है, तो वह भविष्य में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। अन्यथा, वैचारिक और नेतृत्वगत असहमति विपक्षी एकता को कमजोर कर सकती है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष उतना ही आवश्यक है जितना सशक्त सत्तापक्ष; इसलिए जिम्मेदारी और संयम दोनों पक्षों से अपेक्षित हैं।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

राजाकटेल में पंडो जनजाति की जमीन पर कब्जे का आरोप,150 घरों की बसाहट से मचा हड़कंप

सरगुजा में PVTG पंडो परिवारों की पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला गरमाया...

- 12 पंडो परिवारों की जमीन पर कब्जे का दावा,संभागायुक्त ने दिए जांच के निर्देश
- आदिवासी जमीन विवाद ने पकड़ा तूल,राजाकटेल में बड़े पैमाने पर बसाहट का आरोप
- पंडो समाज ने लगाई गुहार : जमीन बचाओ, सुरक्षा दो...
- सरगुजा में विशेष पिछड़ी जनजाति की भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप,प्रशासन हरकत में
- राजाकटेल में भूमि विवाद बना संवेदनशील मुद्दा,कलेक्टर को सौंपी गई जांच...
- पुश्तैनी जमीन पर बाहरी कब्जे का आरोप,पंडो समाज में आक्रोश...

-न्यूज डेस्क-

अंबिकापुर,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत माजा के राजाकटेल बस्ती में पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति की पुश्तैनी जमीन पर बाहरी लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर बड़े पैमाने पर बसाहट किए जाने का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर पहुंच गया है,नगर पालिक निगम अंबिकापुर के पार्षद आलोक दुबे द्वारा इस संबंध में संभागायुक्त सरगुजा को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 12 पंडो परिवारों की जमीन पर बाहरी व्यक्तियों ने कब्जा कर लगभग 150 घर बना लिए हैं, संभागायुक्त कार्यालय,अंबिकापुर से 20 फरवरी 2026 को जारी पत्र (क्रमांक 267848/फाइल नंबर PUBR/538/2026) के माध्यम से कलेक्टर सरगुजा को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायत में क्या लगाए गए आरोप?

शिकायत पत्र के अनुसार राजाकटेल बस्ती में पंडो जनजाति के लोग कई पीढ़ियों से निवास करते आ रहे हैं और उनकी कृषि भूमि पर बाहरी राज्यों–झारखंड, बिहार एवं अन्य क्षेत्रों–से आए लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, आरोप है कि इन कब्जों के बाद वहां स्थायी निर्माण कर लगभग 150 घरों की बसाहट कर दी गई है, शिकायत में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में भूमि क्रय-विक्रय की प्रक्रिया संदिग्ध रही है और कमजोर

अलोक दुबे भाजपा पार्षद

आदिवासी परिवारों को बहला-फुसलाकर या दबाव बनाकर जमीन लिखवाने के आरोप भी सामने आए हैं, ज्ञापन में 12 प्रभावित पंडो परिवारों के नाम और उनके भूमि रकबे का उल्लेख करते हुए जांच की मांग की गई है।

अखबार की खबर भी संलग्न

शिकायत के साथ 12 फरवरी 2026 को प्रकाशित एक समाचार की प्रति भी संलग्न की गई है, जिसमें शीर्षक था–'राजाकटेल में पंडो जनजाति के 12 लोगों की जमीन पर कब्जा, 150 घरों की बसाहट ',समाचार में दावा किया गया था कि प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और भूमि संरक्षण की मांग की है।

थाना लखनपुर में भी दिया गया आवेदन

इसी प्रकरण को लेकर पंडो समाज के लोगों ने थाना लखनपुर में भी आवेदन प्रस्तुत कर सुरक्षा की मांग की है,आवेदन में आरोप लगाया गया है कि भूमि विवाद को लेकर मारपीट,धमकी और सामाजिक तनाव की स्थिति बन रही है,आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बच्चों को स्कूल जाने में बाधा और जान से मारने की धमकी जैसी घटनाओं का भय बना हुआ है,समाज के प्रतिनिधियों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करता तो क्षेत्र में शांति भंग हो सकती है।

संवैधानिक संरक्षण का मुद्दा

पंडो जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग में शामिल है,जिन्हें भारतीय संविधान और विभिन्न भूमि संरक्षण कानूनों के तहत विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, ऐसे में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल भूमि विवाद तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक संरक्षण से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है, विशेषज्ञों का मानना है कि आदिवासी भूमि का हस्तांतरण या कब्जा यदि नियमों के विपरीत हुआ है,तो संबंधित धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई संभव है।

प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर...

संभागायुक्त कार्यालय द्वारा मामले को गंभीर बताते हुए कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए जाने के बाद अब निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं,जांच में यह स्पष्ट होगा कि भूमि हस्तांतरण वैध प्रक्रिया के तहत हुआ या नहीं, कथित कब्जा वास्तविक है या विवादित स्वामित्व का मामला,प्रभावित परिवारों को किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए,यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो अवैध कब्जा हटाने, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और प्रभावित पंडो परिवारों को संरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, फिलहाल,यह मामला सरगुजा जिले में आदिवासी भूमि अधिकार,प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक समरसता के संदर्भ में गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है।

चार किलो गांजा के साथ चार आरोपी गिरफ्तार,कार से करने आए थे डिलेवर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

लग्जरी कार से तीन तस्कर गांजा डिलेवर करने रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र पहुंचे थे। पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 36 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार 26 फरवरी को मुखबिर से पुलिस चौकी रघुनाथपुर को जानकारी मिली की कार क्रमांक सीजी 10 एएल 8571 से तीन व्यक्ति लैलूंगा तरफ से ग्राम गंगापुर निवासी मुरारी लाल चौबे को गांजा डिलेवर करने आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर गांजा तस्करी करने आए हेमसागर यादव पिता पोरना राम यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम नारायणपुर मुड़ापारा थाना लैलुगा जिला रायगढ़, खीरो यादव पिता सुशील यादव उम्र 25 वर्ष निवासी जोरोडा झरिया चौकी कोलेनझरिया थाना तुमला जिला जशपुर, भूपेन्द्र यादव पिता लोचन यादव उम्र 24 वर्ष निवासी पोतरा थाना लैलुगा जिला रायगढ़ व मुरारी लाल चौबे पिता तिरथ राज चौबे उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गंगापुर चौकी रघुनाथपुर थाना लुण्ड्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार से 4 किलो गांजा जब्त किया है। जिसकी कीमत 36 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार, 6 नग मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी रघुनाथपुर उप निरीक्षक आर. एन. पटेल,साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा,प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान,प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा,प्रधान आरक्षक जयदीप सिंह,प्रधान आरक्षक चंद्रभूषण तिवारी,आरक्षक जितेश साहू, मनीष सिंह,उमाशंकर साहू, अमनपुरी,विकास मिश्रा,उमेश खुटिया,इजहार अहमद,इदरीश खान, इजहार अहमद,संजीव चौबे सक्रिय रहे।

पीजी कॉलेज में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आज

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय पीजी कॉलेज में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह-2026 का आयोजन 28 को किया जाएगा। कार्यक्रम पर्यटनमंत्री राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं सांसद चिंतामणि महाराज की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबोध मिंज विधायक लुंड्रा,रामकुमार टोप्पो विधायक,सीतापुर,अनुराग सिंहदेव,अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल, छत्तीसगढ़, विश्वविजय सिंह तोमर,अध्यक्ष,राज्य युवा आयोग, छत्तीसगढ़, मंजूषा भगत महापौर नगर निगम व हरमिंदर सिंह टिन्नी, सभापति नगर निगम,भारत सिंह सिसोदिया भाजपा जिलाध्यक्ष तथा प्रो. रिजवान उल्ला, क्षेत्रीय अपर संचालक,उच्च शिक्षा, सरगुजा संभाग होंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम में सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों,सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों एवं समूहों, क्रीड़ा, एनएसएस और अन्य अकादमिक गतिविधियों में उच्च प्रदर्शन करने वाले एवं विजयी विद्यार्थियों को मैडल,पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जाना है।

मानदेय बढ़ाने की मांग पर उबाल...अंबिकापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं का कलेक्टोरेट घेराव

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

दो दिवसीय हड़ताल के अंतिम दिन शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टोरेट का घेराव किया। धरनास्थल से रैली निकालकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं कलेक्टोरेट पहुंचीं और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मंच के आह्वान पर 26 और 27 फरवरी को सरगुजा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं हड़ताल पर रहीं। इस दौरान अंबिकापुर स्थित एसबीआई शाखा के सामने धरना दिया गया।शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी कुपोषण दूर करने की है, लेकिन

कम मानदेय के कारण वे स्वयं आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। उनका कहना है कि वर्तमान मानदेय से परिवार का भरण-पोषण भी संभव नहीं है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि देश में आईसीडीएस योजना के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं घर-घर जाकर महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। कोविड-19 महामारी, चुनाव ड्यूटी और विभिन्न सर्वेक्षण जैसे अतिरिक्त दायित्व भी उन्होंने निभाए हैं।

मानदेय वृद्धि और शासकीयकरण की मांग...

संयुक्त मंच ने बताया कि वर्तमान में कार्यकर्ताओं को 4500 रुपए और सहायिकाओं को 2250 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है,जो जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है। वर्ष 2018 के बाद से मानदेय में वृद्धि नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई। मंच की प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करना शामिल है। शासकीयकरण तक कार्यकर्ता को 26 हजार रुपए और सहायिका को 22,100 रुपए मासिक वेतन देने, प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की व्यवस्था तथा सेवानिवृत्ति पर पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई है।

9 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी...

संयुक्त मंच ने चेतावनी दी है कि यदि 8 मार्च तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 9 मार्च को प्रदेशभर की लगभग एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं रायपुर पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगी। जिला अध्यक्ष अनूप कुशवाहा, भुनेश्वरी और शैल बानो ने बताया कि मांगों के समर्थन में जिले के विभिन्न स्थानों पर रैली और प्रदर्शन जारी रहेंगे।

रमजान आदेश विवाद...स्पष्टता,जवाबदेही और सार्वजनिक माफी की मांग...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

पवित्र रमज़ान माह के दौरान कथित प्रशासनिक आदेश को लेकर प्रदेश में उत्पन्न भ्रम और विरोधाभास ने राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब सलीम राज द्वारा जारी एक पत्र में रमज़ान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति शासन द्वारा दिए जाने का उल्लेख किया गया था, हालांकि, बाद में राज्य शासन के आधिकारिक विभाग ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, इन परस्पर विरोधी बयानों के बाद अल्पसंख्यक समाज, विशेषकर रोज़ेदारों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई, मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग सरगुजा के अध्यक्ष रशीद अहमद अंसारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरे प्रकरण पर गंभीर चिंता जताई है।

रोज़ेदारों की भावनाओं को ठेस: अंसारी

रशीद अहमद अंसारी ने अपने बयान में कहा कि रमज़ान माह इबादत,सब्र, अमन और भाईचारे का प्रतीक है, ऐसे पवित्र समय में यदि किसी प्रकार की भ्रामक सूचना प्रसारित होती है, तो इससे समाज की भावनाएं आहत होती हैं, उन्होंने कहा कि एक ओर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के पत्र में शासन की अनुमति का उल्लेख किया गया, जबकि दूसरी ओर शासन ने इसे नकार दिया, इस विरोधाभास ने मुस्लिम समाज को गहरी पीड़ा और भ्रम में डाल दिया है।

जनता को सच जानने का अधिकार

अंसारी ने स्पष्ट कहा कि जनता को सत्य

जानने का पूरा अधिकार है, यदि बिना आधिकारिक पुष्टि के कोई आदेश जारी किया गया या सूचना सार्वजनिक की गई,तो यह गंभीर प्रशासनिक चूक है,उन्होंने कहा कि संवेदनशील धार्मिक अवसरों पर किसी भी प्रकार की जानकारी जारी करने से पहले शासन स्तर पर स्पष्टता और आधिकारिक पुष्टि आवश्यक होती है।

सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफ़ी की मांग

प्रेस विज्ञप्ति में तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं जिसमे पूरे मामले पर स्पष्ट और लिखित स्पष्टीकरण जारी किया जाए,जिम्मेदारी तय कर उचित कदम उठाए जाएं, भविष्य में ऐसे संवेदनशील विषयों पर विशेष सावधानी और पारदर्शिता बरती जाए, अंसारी ने कहा कि यदि इस प्रकरण में किसी स्तर पर त्रुटि हुई है,तो संबंधित पक्ष को मुस्लिम समाज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए,ताकि विश्वास बहाल हो सके।

भविष्य में सावधानी की सलाह

रशीद अहमद अंसारी ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष जनाब सलीम राज को सलाह दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र या आदेश जारी करने से पहले पूरी तरह विचार-विमर्श और आधिकारिक पुष्टि सुनिश्चित करें,ताकि समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील

अंसारी ने कहा कि रमज़ान का महीना अमन और भाईचारे का संदेश देता है। ऐसे समय में प्रशासन और संबंधित पदाधिकारियों को विशेष संवेदनशीलता दिखानी चाहिए,उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित पक्ष जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेंगे और समाज के विश्वास को पुनः स्थापित करेंगे।

मामला राजनीतिक तूल पकड़ने की संभावना

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि इस विवाद पर जल्द स्पष्टता नहीं दी गई, तो यह मामला और तूल पकड़ सकता है,चूंकि विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसलिए प्रशासनिक पारदर्शिता और त्वरित स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है,फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें शासन के आधिकारिक स्पष्टीकरण पर टिकी हैं, देखना यह है कि इस विवाद पर कब और किस स्तर से अंतिम स्पष्टता सामने आती है।

कांग्रेस ने नमनाकला में घर-घर पहुंचकर लिया जायजा,दूषित पानी से कई मिले बीमार

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की एवं निगम में निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने शुक्रवार को नमनाकला के खटीक पारा एवं झंझटपारा में घर-घर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। कांग्रेस का कहना है कि लम्बे समय से दूषित जल की सप्लाई एवं साफ-सफाई के अभाव में क्षेत्र में पीलिया, टायफाईड और डायरिया की बीमारी के फैलाव की जानकारी सामने आ रही थी। क्षेत्र का दौरा करने के उपरांत आदित्येश्वर सिंह ने जानकारी दी कि लगभग प्रत्येक घर में एक या एक से अधिक सदस्य दूषित जल जनित इन बीमारियों के शिकार हैं। प्रत्येक घर से मिले इलाज से संबंधित पर्चियों से इस बात की जानकारी मिली है कि लोग पीलिया, टायफाईड और डायरिया जैसे लोगों से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने यह बताया है कि इस क्षेत्र से 2 लोगों के मौत की चर्चा सामने आने के बाद विगत दो-तीन दिनों से पेयजल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कहा कि नावापारा स्वास्थ्य केन्द्र और मेडिकल कॉलेज में जांच के अभाव में आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को अब इलाज में भी कठिनाइयां आ रही है।

बीमार लोगों ने यह शिकायत दर्ज की है कि उन्हें बाहर से जांच आदि कराने में रुपय खर्च करने पड रहे हैं। निजि अस्पतालों में इलाज कराने पर काफी व्यय हो रहा है। उन्होंने ने प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र में मेडिकल शिविर लगाकर बीमार लोगों का निःशुल्क इलाज कराया जाये।

CMYK

जमीन का खेल,फाइलों का मेल: कोरिया में किसका है खेल?

जमीन के खेल में कौन? कोरिया में प्रशासन पर उठे बड़े सवाल...

- भू-माफिया बनाम कानून : कोरिया में सिस्टम पर संदेह
- फाइलों की रफ्तार और सेटिंग का असर?
  कोरिया में राजस्व तंत्र पर सवाल...
- जमीन,दलाल और दफ्तरः कोरिया में
  पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह...
- क्या सबके लिए समान है कानून?
  कोरिया में भू-विवादों पर घमासान...
- तारीख पर तारीख या सेटिंग से समाधान?
- कानून की कुर्सी या प्रभाव का असर?

दफ्तर के दरवाजे खुले, पर न्याय की राह मुश्किल?

राजस्व तंत्र की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल,निष्पक्ष जांच की दरकार...

भू-मामलों में पारदर्शिता बनाम आरोपों का साया...

तहसीलदार और एसडीएम की भूमिका भी घेरे में, पारदर्शिता पर उठे बड़े प्रश्न

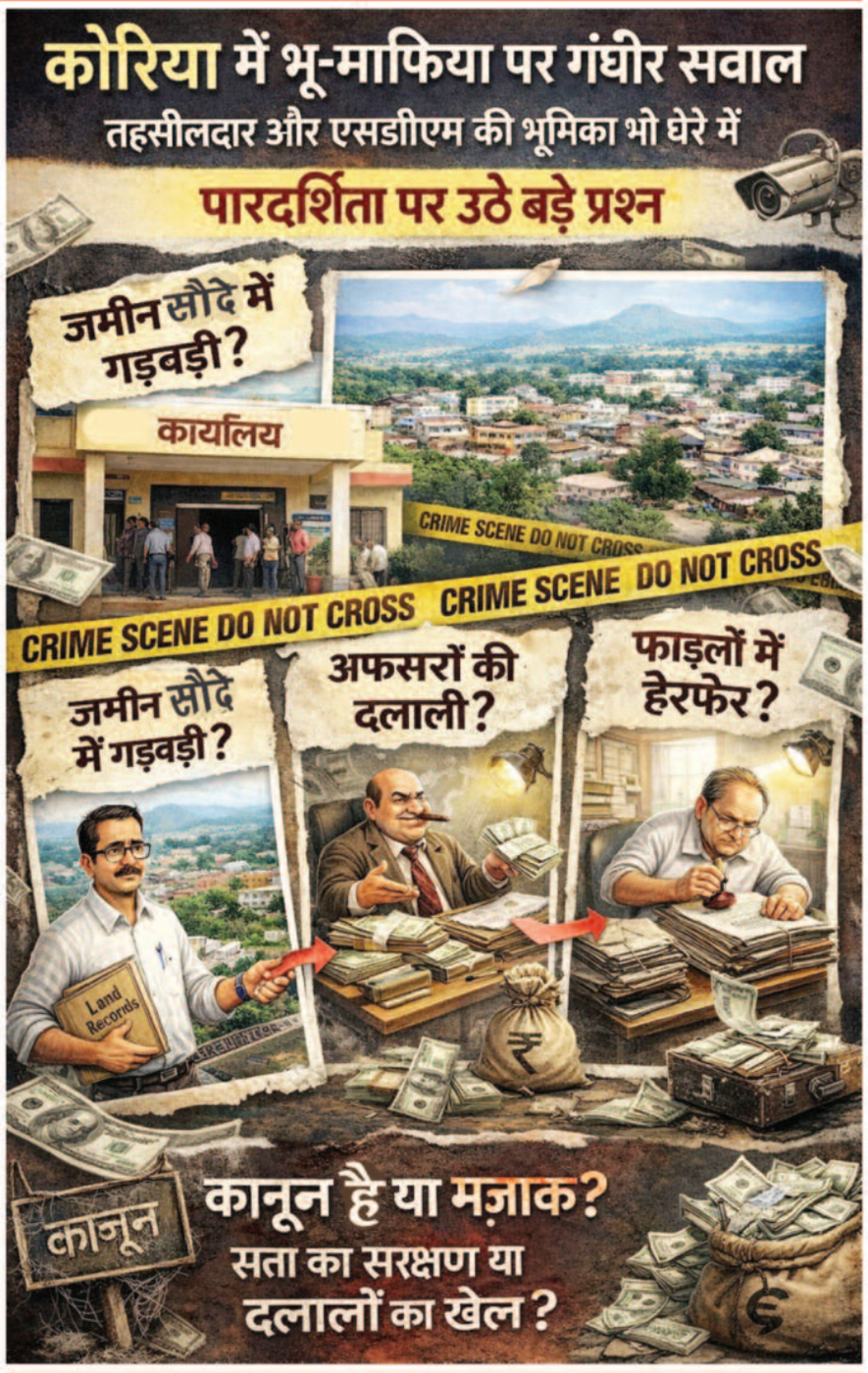

-रवि सिंह-

कोरिया,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में जमीन से जुड़े विवादों और कथित भू-माफिया नेटवर्क को लेकर उठ रहे सवाल अब सीधे प्रशासनिक तंत्र तक पहुंच गए हैं, स्थानीय ग्रामीणों, जमीन मालिकों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजस्व न्यायालयों से लेकर तहसील और एसडीएम कार्यालय तक बिना'सेटिंग' के काम होना मुश्किल हो गया है,इन आरोपों के बीच तहसीलदार और एसडीएम की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है–हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या विभागीय जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, प्रशासन की ओर से भी इन आरोपों पर औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। नोटः- ये उपरोक्त खबर स्थानीय स्तर पर प्राप्त आरोपों, चर्चाओं और दावों पर आधारित है,संबंधित अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समान महत्व के साथ प्रकाशित किया जाएगा।

तहसीलदार और एसडीएम पर क्यों उठ रहे सवाल?

फाइलों की असमान गति...

आम नागरिकों की फाइलें महीनों लंबित रहने के आरोप हैं,जबकि कथित प्रभावशाली पक्षों के मामलों में त्वरित कार्रवाई की चर्चा है। यह अंतर लोगों की शंकाएँ बढ़ा रहा है।

आदेशों की गुणवत्ता पर प्रश्न...

कुछ मामलों में पारित आदेशों की भाषा,तर्क और तथ्यों की व्याख्या पर आपत्तियाँ उठाई गई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ पक्ष उच्च स्तर पर अपील की तैयारी कर रहे हैं।

निगरानी की कमी?

यदि कार्यालयों में दलाल सक्रिय हैं,तो उनकी रोकथाम के लिए ठोस कदम क्यों नहीं दिख रहे–यह भी एक बड़ा सवाल है,क्या विज़िटर लॉग और सीसीटीवी की निगरानी पर्याप्त है? क्या शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो रही है? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

क्या हैं प्रमुख आरोप?

1. **भोले-भाले जमीन मालिक निशाने पर**-ग्रामीणों का दावा है कि सीमांकन,नामांतरण (म्यूटेशन),बंटवारा और रिकॉर्ड दुरुस्ती जैसे मामलों में तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठाया जाता है, कमजोर और अशिक्षित पक्ष को बार-बार तारीख देकर उलझाया जाता है,आपत्तियों और दस्तावेजी कमी के नाम पर फाइलें लंबित रखी जाती हैं,कई मामलों में दबाव बनाकर समझौते की कोशिश की जाती है,कुछ पीड़ितों का कहना है कि वर्षों से चल रहे मामलों में सुनवाई की गति असमान दिखाई देती है।

2. **राजस्व कार्यालयों में दलाल तंत्र सक्रिय?**- स्थानीय स्तर पर यह चर्चा आम है कि कुछ राजस्व कार्यालयों में दलालों की सक्रियता खुले तौर पर दिखाई देती है, आवेदकों को'सुविधा शुल्क' के बदले त्वरित निपटारे का भरोसा दिया जाता है, दस्तावेजों की जांच और फाइल मूवमेंट में बाहरी दखल के आरोप भी लगाए जा रहे हैं,आम नागरिकों का कहना है कि सीधे आवेदन करने पर महीनों इंतजार करना पड़ता है, जबकि 'संपर्क' के माध्यम से काम तेजी से होता है, हालांकि,इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासनिक स्तर पर किसी भी संगठित दलाल नेटवर्क के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है।

3. **पदस्थापना और प्रभाव के दावे**-कुछ सूत्रों का दावा है कि संवेदनशील हलकों में पदस्थापना को लेकर बाहरी प्रभाव काम करता है, हालांकि यह महज चर्चाओं और आरोपों तक सीमित है। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई प्रमाणित जानकारी सामने नहीं आई है।

राजनीतिक संरक्षण के आरोप

स्थानीय चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मामलों में राजनीतिक दबाव का उपयोग किया जाता है, विभिन्न दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं के नाम चर्चा में हैं,लेकिन किसी भी पक्ष ने औपचारिक रूप से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है, यदि ऐसा है, तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता के लिए गंभीर चुनौती है, हालांकि, बिना प्रमाण किसी भी व्यक्ति या संस्था पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा।

प्रशासन की संभावित जिम्मेदारी की स्थिति को देखते हुए प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि...

- संवेदनशील मामलों की समयबद्ध और पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित हो।
- आदेशों की ऑनलाइन उपलब्धता और ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत किया जाए।
- राजस्व कार्यालयों में सीसीटीवी निगरानी और विज़िटर रजिस्टर सख्ती से लागू हो।
- संवेदनशील पदों पर नियमित रोटेशन नीति अपनाई जाए।
- शिकायतों के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र या हेल्पलाइन बनाई जाए, यदि इन उपायों पर अमल होता है, तो जनता का विश्वास बहाल करने में मदद मिल सकती है।

जवाबदेही ही समाधान

कोरिया जिले में जमीन से जुड़े मामलों पर उठ रहे आरोपों ने प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। तहसीलदार और एसडीएम की भूमिका पर उठती शंकाएँ तभी शांत होंगी जब स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्याधारित जांच सामने आएगी, जब तक स्पष्टता नहीं आती, आम नागरिक के मन में यही सवाल गूंजता रहेगा–क्या कानून सबके लिए समान है, या प्रभावशाली लोगों के लिए रास्ते अलग हैं?

नारी शक्ति को समर्पित आकार पब्लिक स्कूल का द्वितीय वार्षिकोत्सव भव्य रूप से सम्पन्न

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों,महिला सम्मान और सामाजिक संदेश से सजा यादगार आयोजन

- नन्हें बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों से गूंजा आकार पब्लिक स्कूल का मंच
- महिलाओं के सम्मान के साथ यादगार बना आकार स्कूल का दूसरा वार्षिकोत्सव
- संस्कार,सम्मान और संस्कृति का संगम बना आकार स्कूल का वार्षिक समारोह
- बच्चों की प्रतिभा और नारी सम्मान ने बांधा समा,आकार स्कूल का आयोजन रहा खास
- आकार इंग्लिस मिडियम स्कूल ने वार्षिकोत्सव में दिया नारी सम्मान का संदेश

-संवाददाता-

कोरिया/पटना,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

आकार शिक्षा समिति द्वारा संचालित आकार इंग्लिस मिडियम स्कूल, पटना में बुधवार को विद्यालय का द्वितीय वार्षिकोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस वर्ष का वार्षिक समारोह 'नारी सशक्तिकरण' की थीम पर आधारित रहा, जिसने कार्यक्रम को केवल सांस्कृतिक आयोजन न बनाकर एक सामाजिक संदेश से जोड़ दिया, विद्यालय परिवार ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि समाज में महिला और पुरुष समान रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा नारी सदैव से पूजनीय और सम्मान की अधिकारिणी रही है।

दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि गीता राजवाड़े (जिला पंचायत सदस्य), अध्यक्षता कर रहीं नविता शिवहरे (नगर पालिका अध्यक्ष बैकुण्ठपुर) तथा गायत्री सिंह (नगर पंचायत अध्यक्ष पटना) द्वारा सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के साथ की गई,विद्यालय प्रबंधक पूनम सोनी एवं आशीष सोनी के साथ समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अतिथियों एवं अभिभावकों का पुष्पगुच्छ,अक्षत-तिलक एवं बैच लगाकर आत्मीय स्वागत किया,कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रविशंकर शर्मा, जवाहर लाल गुप्ता,योगेश शुक्ला,राजेश सोनी,विनोद शर्मा,शंकर सोनी,बिहारी लाल राजवाड़े,अशोक गुप्ता,शिवशंकर राजवाड़े, रामनारायण कुशवाहा सहित जागृति महिला मंडल पटना की पूरी टीम की गरिमामयी उपस्थिति रही।

महिला सशक्तिकरण को समर्पित विशेष सम्मान

विद्यालय की डायरेक्टर पूनम सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय का पहला वार्षिकोत्सव सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान में आयोजित किया गया था, इस वर्ष समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को मंच प्रदान कर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया,उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि हम उन महिलाओं को सम्मान दें जो समाज में अपनी अलग पहचान रखती हैं और जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार एवं समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनकर कार्य किया है, कार्यक्रम में किरण सोनी, नीलू वर्मा,ममता कुशवाहा,मीरा सोनी,शगुफता खान,हिना खान,कामनी राजवाड़े, समुद्री राजवाड़े,अमृता सिंह,संगीता सोनवानी,इतवारी बाई एवं ज्योति दुबे सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को मंच पर सम्मानित किया गया, सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से इन महिलाओं का अभिनंदन किया। कई महिलाएं अपने सम्मान के क्षण को लेकर भावुक भी नजर आई।

नन्हें-मुन्ने बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां

वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहीं, शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों ने छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य, रिकॉर्डिंग डांस,देशभक्ति गीत, समूहगान तथा लघु नाटिका प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया,बच्चों के आत्मविश्वास, मंच संचालन क्षमता और समर्पण ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया,अभिभावक अपने बच्चों की प्रस्तुति को कैमरों में कैद करते नजर आए, पूरा सभागार तालियों और उत्साह से गूंज उठा, कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका श्वेता कश्यप ने प्रभावी एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया। कार्यक्रम की तैयारी में तब्बसुम खान, रोशनी विश्वकर्मा, आफरीन परवीन, हर्षिता राजवाड़े, आफरीन खान, दुर्गावती साहू एवं शिल्पा चौबे का विशेष योगदान रहा, विद्यालय प्रबंधन ने सभी शिक्षकों के परिश्रम की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी।

अतिथियों ने की विद्यालय की पहल की सराहना

मुख्य अतिथि गीता राजवाड़े ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय की यह पहल अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः स्कूल कार्यक्रम केवल बच्चों की प्रस्तुति तक सीमित रहते हैं, किंतु यहां महिलाओं के सम्मान को केंद्र में रखकर कार्यक्रम आयोजित करना समाज के लिए सकारात्मक संदेश है, नविता शिवहरे ने कहा कि समाज में महिलाओं को मंच प्रदान कर उनका सम्मान करना विद्यालय की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है, गायत्री सिंह ने विद्यालय के पिछले वार्षिकोत्सव को याद करते हुए कहा कि आकार इंग्लिस मिडियम स्कूल प्रत्येक वर्ष अपने कार्यक्रम को अलग और सार्थक रूप में प्रस्तुत कर नई मिसाल कायम कर रहा है, बच्चों की प्रस्तुति देखकर उन्हें अपने बचपन की याद ताजा हो गई।

सामाजिक सरोकारों से जुड़ा यादगार आयोजन

आकार पब्लिक स्कूल का द्वितीय वार्षिकोत्सव केवल एक वार्षिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और महिला सम्मान का प्रतीक बनकर सामने आया, विद्यालय ने यह सिद्ध किया कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, संस्कार और समानता के भाव को विकसित करने का माध्यम भी है,कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों,अभिभावकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार समाजोपयोगी विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प दोहराया,नारी शक्ति को समर्पित यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बना,बल्कि पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश छोड़ गया।

CMYK

कुमार चौक में जला पीएम का पुतला: लोकतांत्रिक विरोध या प्रशासनिक चूक ?

पुतला धधका,सवाल भड़के...बैकुंठपुर में युवा कांग्रेस का उग्र संदेश

प्रदेश में भाजपा सरकार, फिर भी पीएम का पुतला दहन–कानून व्यवस्था पर उठे प्रश्न

गिरफ्तारी के विरोध में सियासी आगः कुमार चौक बना टकराव का केंद्र

पुलिस की मौजूदगी में पुतला दहन–क्या था प्रशासन का रुख ?

लोकतंत्र बनाम अनुशासनः कोरिया में विरोध की लपटें और जिम्मेदारी का सवाल

युवा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शनः प्रतीकात्मक विरोध या राजनीतिक रणनीति ?

पुतला जला,राजनीति गरमाईः बैकुंठपुर की घटना से उठे बड़े सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले में शुक्रवार को राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया जब भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यालय से पुतला लेकर निकले कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च के रूप में कुमार चौक पहुंचे। पूरे रास्ते लोकतंत्र बचाओ और राजनीतिक प्रतिशोध बंद करो जैसे नारों से माहौल गूंजता रहा। स्थानीय नागरिकों की भीड़ भी सड़क किनारे जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ।

गिरफ्तारी के विरोध में फूटा आक्रोश...

युवा कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास है, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है,नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाना असंवैधानिक है,यदि जल्द रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन को प्रदेशभर में और तेज किया जाएगा।

कांग्रेस कार्यालय से कुमार चौक तक मार्च

प्रदर्शन की शुरुआत स्थानीय कांग्रेस कार्यालय से हुई, कार्यकर्ता हाथों में बैनर और पुतला लेकर नारे लगाते हुए मुख्य मार्ग से कुमार चौक तक पहुंचे,प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,मार्च के दौरान पुलिस बल मौजूद तो रहा, लेकिन प्रारंभिक चरण में रोकने का कोई सख्त प्रयास नजर नहीं आया,कुमार चौक पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। आग की लपटें उठते ही आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। बताया जाता है कि पुतला लगभग पूरी तरह जल चुका था, उसके बाद ही पानी डाला गया।

पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल ?

घटना के बाद शहर में यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर पुतला दहन से पहले पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं दिखाई,क्या प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति ली गई थी? यदि अनुमति नहीं थी,तो प्रशासन ने पहले ही रोकथाम क्यों नहीं की? क्या पुतला दहन की आशंका के बावजूद सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे? इन सवालों पर पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा की जा रही है, हालांकि,मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में बताया और कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बल तैनात था।

प्रदेश और जिला नेतृत्व की मौजूदगी

आंदोलन का नेतृत्व जिला युवा कांग्रेस ने किया,प्रदेश महासचिव संजीव सिंह काजू,युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राम सजीला यादव,कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुमन दुबे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे,जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह,जनपद सदस्य गणेश सिंह, नगर पालिका बैकुंठपुर उपाध्यक्ष आशीष यादव,जिला प्रवक्ता आशीष डवरे,अविनाश पाठक,जिला महामंत्री दीपक गुप्ता,सौरभ गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल रहे,नेताओं ने एक स्वर में कहा कि संगठन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई तक संघर्ष जारी रखेगा और चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी।

हल्की झड़प,लेकिन स्थिति नियंत्रण में...

पुतला दहन के दौरान सिटी कोतवाली बैकुंठपुर से एसआई महेश कुशवाहा व अमोल सिंह सहित पुलिस बल मौके पर तैनात रहा,प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प की स्थिति भी बनी, लेकिन कोई गंभीर घटना सामने नहीं आई,पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया,आग बुझाने के बाद भी कार्यकर्ता कुछ देर तक नारेबाजी करते रहे।

लोकतांत्रिक विरोध या कानून-व्यवस्था की चुनौती ?

प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद विपक्षी संगठन द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए जाने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, एक ओर कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है,वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सक्रियता और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं,स्थानीय नागरिकों का कहना है कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर आगजनी जैसी गतिविधियों पर समय रहते नियंत्रण होना चाहिए।

आगे क्या ?

युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई नहीं हुई तो जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा,अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाता है और क्या आगे इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई होती है, फिलहाल, कुमार चौक की यह घटना कोरिया जिले की राजनीति में एक नई बहस छेड़ गई है – लोकतंत्र की अभिव्यक्ति बनाम प्रशासनिक जिम्मेदारी।

देवनगर में वर्दी की बेइज्जती

बेल्ट से पिटाई,जबरन डांस और वायरल वीडियो पर पुलिस कब जागेगी ?

वन आरक्षक की सरेआम पिटाई और कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं ?

बेल्ट से पीटा,डांस कराया,वीडियो वायरल...देवनगर कांड में न्याय किसके लिए ?

वन आरक्षक पर विभागीय कार्रवाई,मारपीट करने वालों पर क्या होगी कानूनी कार्रवाई ?

-शमरोज खान-

सूरजपुर,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले के देवनगर बीट अंतर्गत चम्पकनगर नर्सरी क्षेत्र में वन विभाग के एक वर्दीधारी आरक्षक के साथ हुई मारपीट और जबरन डांस करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गंभीर हो गया है, घटना ने न केवल विभागीय अनुशासन बल्कि कानून-व्यवस्था और भीड़तंत्र की प्रवृत्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार,देवनगर बीट में पदस्थ वन आरक्षक सुखदेव पैकरा कथित रूप से एक युवती के साथ नर्सरी क्षेत्र में देखे गए, इसी दौरान कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें घेर लिया, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक वर्दीधारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि उन्हें बेल्ट से पीटा गया,अपमानित किया गया और जबरन डांस करवाया गया, घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया,जिससे मामला सार्वजनिक हो गया,वीडियो सामने आने के बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है।

प्रेम प्रसंग की चर्चा,लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं

स्थानीय स्तर पर घटना को लेकर प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी सामने आई हैं,हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,यह भी स्पष्ट नहीं है कि संबंधित युवती की भूमिका क्या थी और क्या वह इस कथित घटनाक्रम में सहमति से मौजूद थी या किसी दबाव की स्थिति में,ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है,लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

विभाग की कार्रवाई : कारण बताओ नोटिस और मुख्यालय अटैच

मामले के वायरल होते ही वन विभाग हरकत में आया,संबंधित प्रकरण में डीएफओ दुलेश्वर साहू ने वन आरक्षक सुखदेव पैकरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है,नोटिस में यह पूछा गया है कि घटना की जानकारी विभाग को समय पर क्यों नहीं दी गई? ऑन ड्यूटी रहते हुए ऐसी स्थिति कैसे बनी? क्या उन्होंने अपने कर्तव्य और आचरण नियमों का उल्लंघन किया? साथ ही, उन्हें तत्काल प्रभाव से देवनगर बीट से हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

सबसे बड़ा सवालः कानून हाथ में लेने का अधिकार किसे ?

घटना का दूसरा और अधिक गंभीर पहलू यह है कि कुछ युवकों ने कथित रूप से बेल्ट से मारपीट की, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और वीडियो बनाकर वायरल किया, कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करना दंडनीय अपराध है, वर्दीधारी कर्मचारी के साथ सार्वजनिक दुर्व्यवहार गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जबरन वीडियो बनाना और वायरल करना भी आईटी अधिनियम और अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध हो सकता है, ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि वन आरक्षक का आचरण संदिग्ध था भी, तो क्या कुछ युवकों को उन्हें बेल्ट से पीटने और अपमानित करने का अधिकार था?

अब तक एफआईआर क्यों नहीं ?

घटना को लगभग 9 दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी पक्ष द्वारा थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है,यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है,क्या दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश चल रही है? क्या दबाव की स्थिति है? क्या पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी? वायरल वीडियो अपने आप में प्राथमिक साक्ष्य माना जा सकता है। ऐसे में पुलिस चाहे तो स्वयं संज्ञान लेकर जांच प्रारंभ कर सकती है।

प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर नजर

फिलहाल वन विभाग ने अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है,यदि आरोपियों की पहचान हो चुकी है,तो उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक माना जा रहा है,इस घटना ने तीन प्रमुख प्रश्न खड़े किए हैं,क्या आरक्षक ने सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया? क्या युवकों ने कानून हाथ में लेकर गंभीर अपराध किया?क्या पुलिस निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करेगी?

व्यापक संदेशः भीड़तंत्र बनाम कानून व्यवस्था...

देवनगर बीट की यह घटना केवल एक वायरल वीडियो का मामला नहीं है,यह उस बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत भी है,जहां लोग स्वयं न्याय करने की कोशिश में कानून हाथ में ले लेते हैं,यदि किसी सरकारी कर्मचारी की गलती है तो विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया मौजूद है। लेकिन सार्वजनिक रूप से बेल्ट से पिटाई और अपमान–यह कानून के शासन के खिलाफ है।

जांच जारी,कार्रवाई का इंतजार

वन विभाग द्वारा विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है और संबंधित आरक्षक को मुख्यालय अटैच किया गया है,अब निगाहें पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं कि वह वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर क्या ठोस कदम उठाती है, देवनगर बीट की यह घटना आने वाले दिनों में प्रशासनिक सख्ती और कानून व्यवस्था की परीक्षा बन सकती है, जांच जारी है... और पूरे जिले की नजर इस मामले में होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

वरिष्ठ नेताओं के बीच आत्मीय मुलाकात

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने दिग्विजय सिंह से की सौजन्य भेंट

-संवाददाता-

सूरजपुर,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

राजधानी रायपुर में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक सरगर्मियां भी देखने को मिलीं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश और बाहर के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

इसी अवसर पर भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने शिरकत की और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से आत्मीय मुलाकात की, मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक

राजनीतिक परिदृश्य, संगठनात्मक मुद्दों और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। श्री कमरो ने अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काल में दिग्विजय सिंह के प्रशासनिक अनुभवों और राजनीतिक मार्गदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं का अनुभव युवा और सक्रिय नेताओं के लिए प्रेरणास्रोत होता है, कार्यक्रम में मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी गुलाब कमरो ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों को लेकर विचार-विमर्श हुआ, सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात पूरी तरह सौहार्दपूर्ण और पारिवारिक वातावरण में हुई,जिसमें संगठनात्मक एकजुटता और आपसी संवाद पर विशेष बल दिया गया, राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वरिष्ठ और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच संवाद भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0 202602020700 /ब-121/2025-26

प्रस्तावित नक्शा का अंतिम ईश्तहार प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 202602020700 /ब-121/2025-26/ किरण गुप्ता प्रति छग शासन में ग्राम केशवपुर स्थित खसरा नंबर 208/2 रकबा 0.027 हे. भूमि का नक्शा बटांकन कर राजस्व निरीक्षक के माध्यम से मंगाया गया। जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है।

अतः उक्त नक्शा बटांकन में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 13/03/2026 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 25/02/ 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर,छ0ग0

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला- सरगुजा (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0 /अ-06/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुगरीव पति स्व0 अमर दास व अन्य निवासी ग्राम असोला, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम असोला स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 420/2, 421/1, 587/1,607/6, 609/1, 631/1, 651/1 कुल खसरा नंबर 07 कुल रकबा 0.936 हे0 के वर्तमान भूमि स्वामी स्व.अमर दास आठ रघुबीर दास, मनटुरिया पति रघुबीर व फुलकुवंर पुत्री रघुबीर की मृत्यु होने के कारण उनके विधिक वारिशों के नाम पर फौती नामांतरण दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 16/3/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 27/2/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर जिला-सरगुजा छत्तीसगढ़

ईश्तहार

लखनपुर दिनॉक17.02.20.26

प्रति
समस्त ग्रामवासी
ग्राम-रजपुरीकला
तहसील- लखनपुर

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सुखराम प्रजापति आ0 स्व0 सुंदर राम निवासी ग्राम रजपुरीकला तहसील लखनपुर के द्वारा अपने (बाबा) स्व0 विशम्भर प्रजापति की मृत्यु दिनाँक 10-05-2011 को हो जाने से (जन्म / मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ0ग0 जन्म मृत्यु रिज0 नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिस पर दिनाँक 05-03-2026 को सूनवाई की जानी है।

आवेदक/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से पेशी तिथि 05-03-2026 इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनॉक के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

तहसीलदार
लखनपुर
सील — तहसील लखनपुर,

रेंजर आ गए,पर मैदान वही– क्या थमेगा कथित खेल?

कुर्सी हिली,जड़ें नहीं–टाइगर रिजर्व में क्या सचमुच आएगा बदलाव?

प्रभारी का पद घटा, पर पकड़ बरकरार? रेंजर की एंट्री,पर पुराने खिलाड़ी आउट नहीं!

जिला प्रेम या पद की रणनीति? टाइगर रिजर्व में नई पारी की तैयारी

छोटा कद,बड़ा प्रभाव–क्या रुकेगा कथित भ्रष्टाचार?

मैदान बदला नहीं, कप्तान बदला है–अब कैसा होगा खेल?

आगे की राह,यदि वास्तव में सुधार लाना है तो...

सभी विवादित निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच

वित्तीय लेनदेन का ऑडिट

शिकायत निवारण की पारदर्शी व्यवस्था

संपत्ति का सत्यापन

तीन वर्ष की अनिवार्य रोटेशन नीति

निरीक्षण और निगरानी को मजबूत करना

कद छोटा, जिला मोटा
प्रभारी रेंजर की कुर्सी हिली, पर जड़ें वहीं की वहीं!

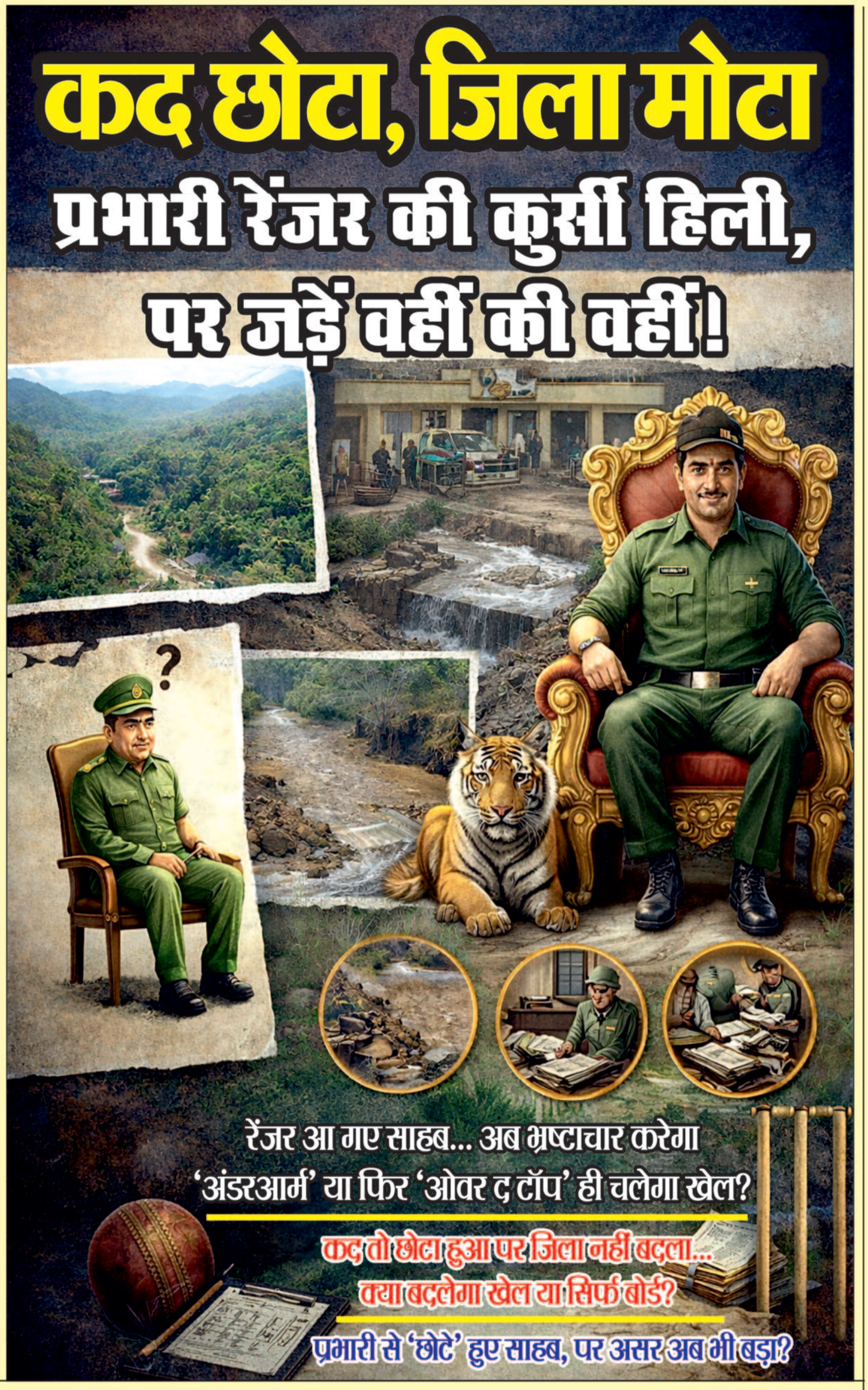

-रवि सिंह-

कोरिया,27 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में इन दिनों प्रशासनिक क्रिकेट का बड़ा रोमांचक मैच चल रहा है, स्कोरबोर्ड पर लिखा है–रेंजर की पदस्थापना हो गई। दर्शकदीर्घा में बैठे लोग ताली बजा रहे हैं,पर ज़रा पिच रिपोर्ट देखिए–प्रभारी रेंजर टुंडे का जिला नहीं बदला, यानी बल्लेबाज़ क्रीज़ पर मौजूद है,बस अंपायर बदल गया है! तबादला सूची आई,नाम भी आया,पर कहानी में ट्विस्ट यह कि प्रभारी रेंजर साहब का कद छोटा हुआ, कैंप नहीं,कुर्सी की ऊँचाई कम हुई है, पर जड़ें अभी भी उसी मिट्टी में मजबूती से गड़ी हैं,अब सवाल यह कि क्या नए रेंजर की निगरानी में खेल साफ-सुथरा होगा या फिर टीमवर्क से रन बनते रहेंगे?

बता दे की गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व क्षेत्र बीते कई महीनों से सुर्खियों में रहा है, गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य,स्टॉप डेम और एनीकट में कथित अनियमितता,पहली बारिश में बह गई सड़क, अवैध गतिविधियों के आरोप,जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग,और अधिकारियों की भूमिका पर उठते सवाल–इन सबके बीच अब लंबे समय से पदस्थ प्रभारी रेंजर टुंडे के जगह अब रेंजर की पदस्थापना तबादला के साथ हो गया है,तबादला सूची जारी होते ही जिले में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस पहल है या फिर केवल प्रशासनिक समायोजन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कथित अनियमितताओं,गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों,अवैध गतिविधियों और प्रशासनिक संरक्षण जैसे गंभीर आरोपों को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार खबरें प्रकाशित होती रही हैं,दैनिक घटती-घटना समाचार-पत्र ने इस मुद्दे को अभियान के रूप में उठाया और अलग-अलग तिथियों पर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित कीं, अब लंबे समय से एक ही क्षेत्र में पदस्थ प्रभारी रेंजर टुंडे का प्रभार बदला सकता है, अब सवाल उठ रहा है की क्या यह केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता है या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस शुरुआत? क्या इस कदम के बाद व्यवस्था में ठोस सुधार होगा? कोरिया जिले की जनता अब केवल अधिकारी परिवर्तन नहीं,बल्कि प्रणालीगत सुधार चाहती है,देखना यह है कि यह तबादला वन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई शुरुआत बनेगा या फिर कुछ समय बाद फिर वही प्रश्न उठ खड़े होंगे।

प्रभारी का 'फुल फ्लैश' दौर : जब मैदान खाली था

कहते हैं,जब मैदान पर एक ही खिलाड़ी हो और गेंद-बल्ला भी उसी के पास हो,तो मैच का नतीजा पूछना नहीं पड़ता,लंबे समय तक नियमित रेंजर की अनुपस्थिति में प्रभारी रेंजर टुंडे ही

मैदान के कप्तान,कोच और स्कोरर रहे,इसी दौर में टाइगर रिजर्व में विकास की गंगा बही...

सड़कें बनीं (पहली बारिश में तैराकी सीख गई),स्टॉप डेम बने (पानी आया तो भावुक हो बह निकले),एनीकट बने (पर टिके कम, दिखे ज़्यादा),मिट्टी-मुरुम की सड़कें बनीं (मिट्टी ने मुरुम से दोस्ती तो की, पर बरसात से नहीं),जनता पूछती रही–साहब,यह विकास है या प्रयोगशाला? जवाब आता–प्रक्रिया चल रही है।

कद छोटा हुआ,क्या प्रभाव भी?

अब रेंजर की नियमित पदस्थापना हो गई है,कागज़ों में प्रभारी का दायरा सीमित माना जा रहा है,पर सवाल यह है कि क्या प्रभाव भी सीमित हुआ है? जिला वही,संपर्क वही,फाइलों की याददाश्त वही–तो क्या बदला? लोग कहते हैं की साहब का कद छोटा हुआ है,पर अनुभव बड़ा है,कहावत है की पुराने खिलाड़ी को पिच की हर दरार याद रहती है।

बढ़ती संपत्ति और बढ़ते किस्से...

जिले में यह चर्चा वर्षों से चल रही है कि प्रभारी रेंजर टुंडे की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई,कोई कहता है मेहनत का फल है,कोई कहता है विकास का कमाल है,जनता पूछती है की इतना विकास जंगल में हुआ या जेब में? जवाब आता है की आरोप बेबुनियाद हैं,आधिकारिक जांच? प्रक्रिया में है,यह प्रक्रिया शब्द प्रशासनिक शब्दकोश का सबसे सुरक्षित कवच माना जाता है।

रेंजर की एंट्री : अब देखरेख सख्त होगी?

अब चूंकि नियमित रेंजर आ गए हैं,उम्मीद है कि निर्माण कार्य उनकी देखरेख में होंगे, यानी अब बल्ला एक के हाथ में,गेंद दूसरे के, जनता उम्मीद कर रही है कि गुणवत्ता जांच होगी,फाइलें खुलेंगी,ऑडिट होगा, और विकास सच में विकास जैसा दिखेगा,पर अनुभवी लोग मुस्कुरा कर कहते हैं–देखते हैं,टीम संयोजन कैसा बनता है।

रामगढ़ की पिच पर नई पारी?

सूत्रों का कहना है कि रामगढ़ क्षेत्र में रेंजर की पदस्थापना अभी नहीं हुई है,अब चर्चा है कि प्रभारी रेंजर टुंडे वहां नई पारी खेलने की कोशिश कर सकते हैं,अगर ऐसा हुआ तो कद छोटा होने का असर ज्यादा दिन नहीं रहेगा,क्योंकि मैदान बदल जाएगा,पर खिलाड़ी वही रहेगा,यह चर्चा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं,पर अफवाहों की दुनिया में भी धुआँ बिना आग के नहीं उठता–ऐसा लोग कहते हैं।

प्रमोशन की आहट और जिला प्रेम

सूत्र बताते हैं कि अगले 5-6 महीनों में प्रमोशन की संभावना है, कहते हैं,रेंजर बनकर इसी जिले में रहना उनका सपना है, जिला भी शायद कह रहा हो की जाने भी दो यारों! जनता पूछती है की लंबे समय से जमे अधिकारी को प्रमोशन के बाद भी यहीं रखना क्या स्वस्थ परंपरा है? जवाब फिर वही–प्रशासनिक विवेक।

जांच की मांगः पुरानी फाइलें खुलेंगी?

अब यह मांग तेज हो रही है कि प्रभारी रेंजर के कार्यकाल में हुए सभी निर्माण कार्यों की जांच हो,जांच के बिंदु,तकनीकी गुणवत्ता,वित्तीय पारदर्शिता,ठेका प्रक्रिया,संपत्ति सत्यापन,यदि जांच हुई और रिपोर्ट सार्वजनिक हुई,तो शायद जंगल में पहली बार पारदर्शिता नामक पक्षी दिखे।

तीन साल की रोटेशन नीति : क्यों जरूरी?

वन विभाग में वर्षों तक एक ही जगह जमे रहना कई तरह के रिश्ते बना देता है,रिश्ते फाइलों से, ठेकेदारों से,व्यवस्था से,इसलिए मांग है कि हर तीन साल में अनिवार्य रोटेशन हो,वरना जंगल का नियम प्रशासनिक नियम पर भारी पड़ जाता है।

जनता की उम्मीद : अब अंडरआर्म बॉलिंग नहीं...

लोगों का कहना है कि अब सीधी बॉलिंग होनी चाहिए,मतलब की साफ काम,साफ हिसाब,साफ जवाब टाइगर रिजर्व कोई निजी लीग नहीं, सार्वजनिक संपत्ति है,यहां विकास का मतलब फोटो नहीं, टिकाऊ संरचना होना चाहिए।

क्या सच में रुकेगा खेल?

प्रभारी रेंजर का कद छोटा हुआ है पर यह प्रशासनिक तथ्य है, पर जिला वही है यह भी उतना ही बड़ा तथ्य है,यदि जांच नहीं हुई, जिला परिवर्तन नहीं हुआ,रोटेशन नीति लागू नहीं हुई,तो खेल जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता,हाँ,कुछ समय के लिए रन रेट कम हो सकता है।

मैच अभी बाकी है...

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में प्रशासनिक बदलाव जरूर हुआ है, पर क्या यह निर्णायक है? जनता अब केवल तबादला नहीं, पारदर्शिता चाहती है,केवल कद छोटा करना नहीं,व्यवस्था बदलना जरूरी है, वरना इतिहास गवाह है की चेहरे बदलते हैं, पर कहानियाँ वही रहती हैं, अब देखना यह है कि नया रेंजर इस पिच पर नियमों से खेलेगा या फिर पुरानी रणनीति जारी रहेगी, जंगल इंतजार कर रहा है कि विकास सच में हरा दिखे,और भ्रष्टाचार केवल अखबार की हेडलाइन बनकर रह जाए।

पूर्व में प्रकाशित प्रमुख खबरें: दैनिक घटती-घटना में बीते महीनों में प्रकाशित खबरों ने पूरे मामले को सार्वजनिक विमर्श का विषय बना दिया था,प्रमुख शीर्षक रहे...

टाइगर रिजर्व या भ्रष्टाचार का अभयारण्य?

गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में भ्रष्टाचार का काला तालाब?

क्या भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व?

गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों के चक्कर में टाइगर रिजर्व का कैसे होगा विकास...

अनियमितताएं चरमोत्कर्ष पर...

जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो...

मनेन्द्रगढ़ वन मंडल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर?

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता हुआ...

स्टॉप डेम और एनीकट निर्माण में तकनीकी खामियां...

पहली बारिश में सड़क ध्वस्त...

सरकारी राशि के उपयोग पर सवाल,शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं...

अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध...

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र....सदन में गरमाया बजट में सम्मिलित कार्यों को वित्तीय स्वीकृति देने का मुद्दा,वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट

रायपुर,27 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने बजट में सम्मिलित कार्यों को वित्तीय स्वीकृति देने का मुद्दा उठाया। इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉक आउट किया। कांग्रेस विधायक संगीता सिंह ने प्रश्नकाल में बजट में सम्मिलित कार्यों को वित्तीय स्वीकृति देने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि अब तक कौन-कौन से कार्य वित्त विभाग के पास लंबित है और क्यों? इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्य वित्त विभाग में लंबित नहीं है। इस पर विधायक ने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के पूरे काम वित्तीय विभाग में पेंडिंग होने की बात कही। इस पर मंत्री ने कि हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हम कोई कार्य पेंडिंग न रखकर उसे ज्यादा से ज्यादा कर सके। इसके लिए नवीन मद की राशि भी बढ़ा दी गई है। मशीन उपकरण को 50 हजार से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिए हैं। प्रशासकीय स्वीकृति 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान बहुत ज्यादा होता है। सरकार प्राथमिकता से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करती है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि बालोद के बारे में तो बताइए। मंत्री ने कहा कि बालोद के लिए भी वित्त विभाग में कोई फाइल लंबित नहीं है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी से वित्त विभाग की फाइल मांगकर उसे स्वीकृत करेंगे क्या? मंत्री ने कहा कि हर कार्य की एक प्रक्रिया होती है। विधायक ने कहा कि 18 करोड़ को जो स्वीकृति है, वो तो आप दे सकते हैं। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि विभाग सबकुछ तो करता है। भूपेश बघेल ने कहा कि वित्त मंत्री जी काफी उदार है। आप घोषणा कर दीजिए, हम भी आपका स्वागत कर देंगे। मंत्री ने दोहराया कि सबकी एक पद्धति होती है। भूपेश बघेल ने कहा कि आप सब कह दे रहे हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉक आउट किया।

पशुओं के रख-रखाव पर मिली जानकारी से नाराज विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कसा तंज,कहा...गौमाता के नाम से वोट मांगा है तो घोषित करें उन्हें राष्ट्रमाता

विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक कुंवर सिंह निषाद ने राज्य में घुमंतू पशुओं के रख-रखाव और संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का मुद्दा उठाया। मंत्री द्वारा दी गई जानकारी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग गौमाता के नाम से वोट मांगा है, तो उन्हें राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाना चाहिए। दरअसल, विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि घुमंतू पशुओं के रख-रखाव संरक्षण के लिए राज्य में कौन-कौन सी योजना चल रही है। मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि पशुधन विभाग से जो योजना चल रही है, उसमें आदर्श गोधाम, गोकुल धाम गौ अभ्यारण योजना है। विधायक ने इस पर सवाल किया कि कितने पशुओं का रख-रखाव योजना के माध्यम से हो रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि गोधाम योजना के तहत 620 पशुओं के संरक्षण ओर व्यवस्थाओं के लिए इतंजाम किया गया है। कई सारे जगह में कार्य प्रक्रियाधीन हैं, उसे जल्द चालू करेंगे। इस पर विधायक ने सवाल किया कि 620 पशुओं के चारा-पानी की व्यवस्था सरकार कर रहा है, या कोई और कर रहा है? इस पर मंत्री ने बताया कि 36 गोठानों में गौधाम की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई गई है। जब राशि पंजीकृत संस्थाओं को दिया जाता है, तो वो उसका सही उपयोग किया जाता है। इस पर विधायक ने स्वीकृत राशि निरंक होने की जानकारी दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 36 गोठानों में पशुओं को रखने का व्यवस्था करेंगे। केवल आरोप लगाने से नहीं होता। प्रदेश में घुमंतू आवारा पशुओं को भी हम संरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। विधायक ने सवाल किया कि ये गोठान कहां-कहां संचालित हैं। मंत्री ने बताया कि दो गोठान तखतपुर-बिलासपुर और साजा-बेमेतरा में संचालित हैं। और राजपुर-मरवाही में। इस तरह से 11 जगह गोठान खुले हैं, और 3 जगह संचालित हैं। विधायक ने इस पर सवाल किया कि संचालित करने के लिए अभी ठोस कार्य योजना नहीं है? मंत्री ने बताया कि जितने भी घुमंतू पशु हैं, वह नगरीय क्षेत्र में है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है। रख-रखाव हमारा काम नहीं है संरक्षण से संबंधित कार्य है हमारा

सत्ता पक्ष के विधायकों के तल्ख तेवर परीक्षा में नकल का मुद्दा उठाया

सदन में सत्ता पक्ष के विधायक प्रमोध मिंज, अजय चंद्राकर, रिकेश सेन ने परीक्षा में नकल और परीक्षा केंद्र से वंचित किए जाने को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया। विधायकों ने तल्ख तेवर में कहा- बच्चे 15 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दे रहे। परीक्षा केंद्र से वंचित रखने से उन्हें परेशानी हो रही। ये केंद्र सरकार के नियमों का उल्लंघन है। मंत्री गजेंद्र यादव ने जवाब दिया कि अगले शिक्षा सत्र से व्यवस्था ठीक होगी।

विपक्ष ने विकास कार्यों की स्वीकृति मांगी,हंगामा हुआ

कांग्रेस विधायकों के सवाल। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब पर हंगामा हुआ।

- विधायक उमेश पटेल- रायगढ़ जिले में संचालित उद्योगों में कितने मामले अवैध फ्लाईऐश डंप के आए और कितने पर कार्रवाई हुई।
- वित्त मंत्री ओपी चौधरी- आपकी सरकार की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा कार्रवाई हुई, हमने ट्रांसपोर्ट्स की धरपकड़ की है।
- पूर्व सीएम भूपेश बघेल- जिसको आप निरंक बता रहे, उस समय तो आपकी सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। वित्त मंत्री के जवाब पर सदन में हंगामा हुआ। हंगामे के बाद विपक्ष का पहला वॉकआउट।

सरेंडर नक्सलियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही

मुख्यधारा में लौटे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार कर रही सतत प्रयास : सीएम साय

माओवाद की विचारधारा त्यागकर संविधान की राह अपनाने वाले 120 पुनर्वासित युवाओं के दल ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचकर जनतांत्रिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। युवाओं ने सदन की कार्यवाही को करीब से देखा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा। विधानसभा का यह शैक्षणिक भ्रमण उनके लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक अनुभव साबित हुआ। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आत्मीय मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने सभी का 'जय जोहार' के साथ स्वागत करते हुए कहा कि पुनर्वास का निर्णय लेने वाले सभी साथियों का राज्य सरकार हृदय से अभिनंदन करती है। उन्होंने कहा कि सरकार पुनर्वासित युवाओं की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी पुनर्वासित युवा समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें और आत्मनिर्भर बनें। इसी उद्देश्य से पुनर्वास नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंसा का मार्ग छोड़कर आज संविधान के मंदिर में खड़े होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का साक्षी बनना इस बात का प्रमाण है कि बदलाव संभव है। मुख्यमंत्री साय ने युवाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और शासन की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा 'गन'तंत्र का रास्ता छोड़कर गणतंत्र की मुख्यधारा में लौटे हैं, उनका राज्य सरकार हृदय से स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि संविधान का मार्ग ही शांति, विकास और समृद्धि का मार्ग है। राज्य सरकार पुनर्वासित युवाओं के सम्मानजनक जीवन, रोजगार और कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनेंगे और अन्य लोगों को भी मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक किरण देव तथा सुशांत शुक्ला ने भी पुनर्वासित युवाओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि शासन उनके साथ दृढ़ता से खड़ा है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत

बिलासपुर,27 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत संबलपुरी के पास नेशनल हाईवे पर शुक्रवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उपचार सिम्स अस्पताल में जारी है। सकरी थाना पुलिस के अनुसार, गुरुवार देर रात करीब दो बजे ट्रेलर (सीजी 11 बीडी 9044) सकरी-रतनपुर मार्ग से रायपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रेलर चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन रॉन्ग साइड में पहुंच गया। सामने से आ रही स्कॉर्पियो (सीजी 04 एमक्यू 4220) से उसकी आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रेलर ने पास खड़े एक अन्य ट्रेलर को भी अपनी चपेट में ले लिया और पलट गया, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। रायपुर-रतनपुर मार्ग राज्य का प्रमुख यातायात मार्ग होने के कारण घटना के बाद कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को मौके पर बुलाया। सकरी थाना पुलिस एवं राहत दल ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक चार लोगों की मौत हो चुकी थी। स्कॉर्पियो में कुल पांच लोग सवार थे, जो यादव ढाबा में आयोजित पारिवारिक शादी की 25वीं सालगिरह कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान छत्रपाल रात्रे (37) निवासी ग्राम कुवागांव थाना तखतपुर, विशाल लहरे (25) निवासी बिरगहनी थाना जरहागांव जिला मुंगेली, अनमोल लहरे (14) निवासी बिरगहनी जिला मुंगेली तथा देवेंद्र मिरी (32) निवासी सीपत के रूप में की गई है। वहीं हादसे में घायल प्रकाश रात्रे को गंभीर अवस्था में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

आरएसएस पर आधारित फिल्म शतक छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री

सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा,कहा...'शतक' केवल फिल्म नहीं,विचारों की यात्रा

रायपुर, 27 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 26 फरवरी को राजधानी रायपुर स्थित जोरा मॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म शतक के स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि उन्होंने मंत्रिमंडल के साथी रामविचार नेताम, केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, राजेश अग्रवाल और विधायकों व जनप्रतिनिधियों के साथ फिल्म शतक देखी। साय ने कहा कि 'शतक' राष्ट्रनिर्माण में संघ की सतत साधना का सजीव चित्रण है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की प्रेरक गाथा जन-जन तक पहुंचे और नई पीढ़ी को राष्ट्रसेवा की भावना से प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया है।

'शतक' केवल फिल्म नहीं, विचारों की यात्रा

फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 'शतक' सिर्फ एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं है,बल्कि यह राष्ट्रप्रेम,जनसेवा और अनुशासन की उस परंपरा को दर्शाती है, जिसने देश को दिशा देने का कार्य किया है। यह फिल्म संघ की वैचारिक यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है।

छत्तीसगढ़ में टैक्स-फ्री करने का निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि संघ की प्रेरक गाथा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और विशेषकर युवा पीढ़ी राष्ट्रसेवा की भावना से जुड़ सके, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने फिल्म 'शतक' को छत्तीसगढ़ में टैक्स-फ्री करने का निर्णय लिया है।

संघ की शताब्दी यात्रा का स्मरण

सीएम साय ने कहा कि पूजनीय डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के विचारों से प्रारंभ हुई संघ की यह यात्रा पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के नेतृत्व में और अधिक संगठित व सशक्त हुई। उन्होंने कहा कि संघ का सौ वर्षों का इतिहास लाखों स्वयंसेवकों के त्याग, तपस्या और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का प्रमाण है।

शिक्षा, सेवा और समरसता में संघ की भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिक्षा, सेवा और सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य किया है। आपदा और संकट के समय संघ कार्यकर्ताओं की सेवा भावना समाज के लिए संबल बनी है।

शासन को भी मिलती है राष्ट्रसेवा से प्रेरणा

सीएम साय ने कहा कि जनसेवा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की यही सोच शासन के कार्यों में भी मार्गदर्शक बनती है। उन्होंने विश्वास जताया कि फिल्म 'शतक' समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवाओं को राष्ट्रनिर्माण के लिए प्रेरित करेगी।

बिलासपुर में 'क्राइम ब्रांच' अफसर बनकर की ठगी...रिटायर्ड-कर्मचारी को लुटेरों का दिखाया डर,3 तोला सोने की चेन और अंगूठी लेकर कागज में पत्थर थमाया

बिलासपुर,27 फरवरी 2026। बिलासपुर में ठगों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर एक रिटायर कर्मचारी को पहले डराया। फिर लूट की आंशका पर सोने की चेन और अंगूठी उतरवा लिए, जिसके बाद गहनों को कागज में लपेट कर घर ले जाने की बात कही। इस दौरान चकमा देकर ठगों ने जेवर खुद रख लिए और बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी को कागज की पुड़िया में पत्थर थमाकर भाग गए। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। कुम्हारपारा के रूखमणी विहार निवासी हरि प्रसाद पटेल ने पुलिस को बताया कि वे 25 फरवरी की दोपहर लिंक रोड स्थित अपने बेटे की मिलन किराना स्टोर दुकान पर खाना पहुंचाने गए थे। दोपहर में करीब 3 बजे स्कूटी (नंबर सीजी 10 एएच 7182) से घर लौटते समय समता कॉलोनी के पास मगरपारा क्षेत्र के पास पहुंचे थे। इस दौरान तभी काले रंग की बाइक पर सवार दो युवकों ने उन्हें ओवरटेक कर रोका।

गांजा तस्करी के मामले में तीन को 20 साल कैद आरोपियों के पास से 50 किलो गांजा हुआ था जब्त

रायपुर,27 फरवरी 2026। महासमुंद से रायपुर गांजा तस्करी करने के मामले में तीनों आरोपियों को 20 साल कैद और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने सुनाया है। मामला अगस्त 2024 में मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में पकड़ी गई 50 किलो से अधिक गांजा खेप से जुड़ा है। विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि अदालत ने इस मामले में सतीश अग्रवाल,कामेश्वरी गोस्वामी और सुभाष पटेल को दोषसिद्ध मानते हुए कठोर सजा सुनाई है।

आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर न करे सरकार...गर्मियों में चलाए जा रहे नक्सल अभियानों में विशेष सावधानी बरती जाए : दीपक बैज

रायपुर,27 फरवरी 2026। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर राज्य सरकार को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना ऑपरेशन चलाए, कांग्रेस को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर न किया जाए। बैज ने कहा कि गर्मी के मौसम में जंगल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी इमली, महुआ, तेंदूपत्ता और लकड़ी जैसे संसाधन जुटाने के लिए जंगल जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए ताकि निर्दोष ग्रामीण किसी कार्रवाई का शिकार न हों। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में भी आदिवासियों को नक्सली बताकर मुठभेड़ में मारे जाने के मामले सामने आए हैं।

14 अगस्त 2025 : केशकाल का मामला

कांग्रेस ने 14 अगस्त 2025 को केशकाल क्षेत्र के कोहकामेटा गांव में हुई घटना का जिक्र किया। पार्टी नेताओं के अनुसार, चार युवक (उम्र 23-24 वर्ष) जंगल गए थे। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें नक्सली बताकर गोली मार दी। दावा था कि युवक अपनी पहचान बता रहे थे और मोबाइल और आधार कार्ड भी दिखाए थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। बाद में घटना को नक्सली मुठभेड़ बताया गया, जबकि आसपास गोलीबारी के स्पष्ट निशान नहीं मिले। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मृतक के पिता को भी शुरुआत में अलग जानकारी दी गई, जिसे परिवार ने मानने से इनकार कर दिया।

बीजापुर का दो साल पुराना मामला : कांग्रेस ने बीजापुर जिले के पीडिया गांव की घटना का भी हवाला दिया, जहां दो वर्ष पहले 12 आदिवासियों के मारे जाने का मामला सामने आया था। कांग्रेस की जांच समिति ने तब आरोप लगाया था कि मारे गए लोग नक्सली नहीं, बल्कि स्थानीय आदिवासी थे। उनका कहना था कि ग्रामीण रोज की तरह तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गए थे, जहां उन्हें घेरकर गोली चलाई गई। कांग्रेस ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की थी।

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल...आईएएस कुलदीप शर्मा बलौदाबाजार कलेक्टर,11 अफसरों को सरकार ने दी नई जिम्मेदारियां

रायपुर,27 फरवरी 2026। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। इसके साथ ही कुलदीप शर्मा को बलौदाबाजार का नया कलेक्टर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डॉ. सीआर प्रसन्ना (2006 बैच), सचिव सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ आयुक्त सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं कुलदीप शर्मा (2014 बैच), रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं को अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पद पर पदस्थ किया गया है। तीर्थराज अग्रवाल को उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बनाया गया है, साथ ही उन्हें धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। लीना कोसम को परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर पद पर यथावत रखा गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 2016 के तहत वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष घोषित किया गया है। इसी प्रकार सौमिल रंजन चौबे (उप सचिव, कृषि विभाग), बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई (अपर कलेक्टर, नारायणपुर), सुमीत अग्रवाल (आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग) और संदीप कुमार अग्रवाल (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर) को यथावत पदस्थ किया गया है।

आशीष कुमार टिकरिहा को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन नियुक्त किया गया है, जिसे वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष दर्जा दिया गया है। वहीं ऋषभ कुमार पाराशर (उप सचिव, वित्त) यथावत रहेंगे तथा तरूण कुमार किरण को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय कोरबा पदस्थ किया गया है।

5000 शिक्षकों की भर्ती से युवाओं को मिलेगा अवसर,शिक्षा व्यवस्था होगी सुदृढ़ : सीएम साय

रायपुर,27 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की संभावित तिथियां घोषित हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि व्यापम द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर 2026, शिक्षक की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 एवं व्याख्याता की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को संभावित है। मुख्यमंत्री साय ने सभी अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के साथ किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। युवा प्रदेश के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बनाने में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

CMYK

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25
वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

किसान हितैषी विष्णु सरकार

वृहद किसान सम्मेलन

दो साल में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के खाते में **₹1.50 लाख करोड़** से अधिक की राशि अंतरित

- **33,431 करोड़ रूपए** समर्थन मूल्य का भुगतान
- **3100 रूपए** प्रति क्विंटल की दर से राज्य के किसानों से प्रति एकड़ **21 क्विंटल धान खरीदी**
- वर्ष 2025-26 में **141.04 लाख मीट्रिक टन** की धान खरीदी
- **11,000 रुपए** प्रति एकड़ की दर से दलहन, तिलहन,मक्का,कपास, कोदो-कुटकी-रागी पर भी इनपुट सब्सिडी

जीएसटी 2.0 लागू होने से **कृषि उपकरण** हुए सस्ते

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
दो साल में 26 लाख किसानों को ₹10,784 करोड़ वितरित

रबी सीज़न 2023-24 से 2025-26 के बीच
- खाद की खपत 41,84,850 मीट्रिक टन
- खाद सब्सिडी ₹7593.22 करोड़

कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण समारोह

सभी 146 विकासखण्डों में आयोजन

25.28 लाख किसानों के खातों में

₹10,324 करोड़

की आदान सहायता राशि होगी वितरित

बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान

- **₹600 करोड़** — दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
- **₹5,500 करोड़** — विद्युत पम्पों हेतु बिजली सब्सिडी
- **₹820 करोड़** — प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- **₹250 करोड़** — इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान
- **₹170 करोड़** — उद्यानिकी विश्वविद्यालय
- **₹170 करोड़** — एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम
- **₹150 करोड़** — एकीकृत बागवानी विकास मिशन

28 फरवरी 2026

खेल मैदान रहंगी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संवाद 47030/58

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)